

मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का बढ़ेगा दायरा, किसानों के मेधावी बच्चों को मिलेगा लाभ : योगी

लखनऊ, संवाददाता । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के मेधावी बच्चों के लिए चल रही मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके. शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 172वीं बैठक हुई. बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए 3025.49 करोड़ के बजट सहित किसान कल्याण, कृषि विपणन और मंडी व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. मुख्यमंत्री ने प्रदेश की मंडियों के आधुनिकीकरण और पुनरोद्धार के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सभी मंडियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए, ताकि किसानों को बेहतर, पारदर्शी और सुविधाजनक तरीके से अपनी उपज बेचने की व्यवस्था मिल सके. मंडियों में पेयजल, स्वच्छता, रोशनी



समेत सभी जरूरी सुविधाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया. योगी ने मंडी स्थलों पर पीपीपी मॉडल के तहत कृषि उपज प्रसंस्करण इकाइयां लगाने को बढ़ावा देने के निर्देश दिए. इसके लिए नियमों को ज्यादा आसान और निवेश के अनुकूल बनाने को कहा गया. इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम और मूल्य संवर्धन का लाभ मिल सकेगा. साथ ही

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. मुख्यमंत्री ने ज्यादा से ज्यादा मंडियों को ई-नाम यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म से जोड़ने के निर्देश दिए. उन्होंने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन से अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने और हर जिले में ऑर्गेनिक उत्पादों के सर्टिफिकेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा. बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26

के संशोधित आय-व्यय अनुमान और वर्ष 2026-27 के बजट को मंजूरी दी गई. वर्ष 2026-27 के लिए ६2228.59 करोड़ की अनुमानित प्राप्तियों और 3025.49 करोड़ के खर्च का प्रावधान स्वीकृत किया गया. बैठक में बताया गया कि प्रदेश की मंडी समितियों की आय वर्ष 2024-25 में ६1991.33 करोड़ थी, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर ६2305.80 करोड़ हो गई. इस तरह मंडी

समितियों की आय में 15.79 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई. बजट में मंडी स्थलों के निर्माण और विस्तार, संपर्क मार्गों के निर्माण और मरम्मत, ग्रामीण हाट, किसान बाजार, गोवंश आश्रय स्थल, छात्रावास निर्माण, मंडी समितियों के लिए जमीन खरीद और अन्य विकास कार्यों के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है. पहले से मंजूर निर्माण कार्यों को तेजी देने के लिए 1212.02 करोड़ का प्रावधान किया गया है. संचालक मंडल ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना और मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना की अवधि 1 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 30 जून 2030 तक करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. दोनों योजनाओं के संचालन के लिए वर्ष 2026-27 के बजट में ६30 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

नयी दिल्ली, एजेंसी । लोकसभा ने शुक्रवार को जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाले विधेयक को विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया। राज्यसभा में बीते 29 जुलाई को यह विधेयक पारित किया गया था। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच जन्म और मृत्यु का पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 को पारित करने के लिए पेश किया। इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पर अपने संशोधन भी पेश नहीं किए। बीते 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दी थी और



इसे 29 जुलाई को सदन में पेश किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की धारा 13(3) में और संशोधन करना है, ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके। मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण एक वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है, तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश

की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर दो-स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। विधेयक पारित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि यह इतना महत्वपूर्ण विधेयक है और हम चाहते थे कि सब सदस्य इसके भाग लें। उन्होंने कहा कि बार-बार अनुरोध के बावजूद विपक्ष के साथियों ने विधेयक पर चर्चा में भाग नहीं लिया और अब उन्हें सदन से बाहर जाकर यह नहीं कहना चाहिए कि बिना चर्चा के क्यों पारित किया।

सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान

राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, रिस्पॉन्स ग्रुप बनाकर जारी रहेगा छात्र आंदोलन

नयी दिल्ली, एजेंसी । कॉंग्रेस जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने स्पष्ट किया है कि उनका संगठन किसी राजनीतिक दल में तब्दील नहीं होगा और न ही वे भविष्य में कोई राजनीतिक पार्टी जॉइन करेंगे। उनका कहना है कि आंदोलन का उद्देश्य सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि छात्रों और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि आगे एक रिसपॉन्स ग्रुप बनाया जाएगा, जो शिक्षा, रोजगार और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर लगातार आवाज उठाएगा। हाल ही में दिए एक विस्तृत इंटरव्यू में अभिजीत दीपके ने नीट पेपर लीक अमेंडमेंट बिल, छात्र आंदोलन, सरकार की भूमिका, विपक्ष के समर्थन, सोनम वांगचुक से मुलाकात की कोशिश और आंदोलन की आगामी रणनीति पर खुलकर अपनी बात रखी।



अभिजीत दीपके का कहना है कि संसद से पारित पेपर लीक अमेंडमेंट बिल का मुख्य फोकस पेपर लीक होने के बाद की कानूनी कार्रवाई पर है, जबकि असली जरूरत ऐसी व्यवस्था बनाने की थी जिससे पेपर लीक की घटनाएं ही न हों। उन्होंने कहा कि सरकार ने सजा और जुर्माने की अवधि बढ़ा दी है, लेकिन इससे यह संदेश भी जाता है कि सरकार पहले से मानकर चल रही है कि पेपर लीक की घटनाएं होती रहेंगी। उनके अनुसार छात्रों की सबसे

बड़ी मांग परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाना थी। दीपके ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित फास्ट-ट्रैक कोर्ट की पहल का जिक्र करते हुए कहा कि यदि सरकारी एजेंसियां पहली सुनवाई में ही पूरी तैयारी के साथ उपस्थित नहीं होतीं तो कानून का प्रभाव सीमित रह जाता है। उन्होंने कहा कि केवल कठोर कानून बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि ईमानदार राजनीतिक इच्छाशक्ति और जवाबदेही तय करना अधिक जरूरी है। उन्होंने बताया कि आंदोलन की प्रमुख मांगों में पेपर लीक से प्रभावित परिवारों को उचित आर्थिक

सहायता और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करना शामिल था। दीपके के अनुसार सरकार ने बातचीत में आश्वासन तो दिया, लेकिन अब तक पीड़ित परिवारों को राहत नहीं मिली है। उनका कहना है कि यदि बड़े सरकारी फैसलों के लिए संसाधन तुरंत जुटाए जा सकते हैं तो प्रभावित परिवारों की मदद में देरी नहीं होनी चाहिए। अभिजीत दीपके ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय में हुए बदलाव छात्र आंदोलन के दबाव का परिणाम माने जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति और मंत्रालय के कुछ प्रशासनिक निर्णयों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था में केवल चेहरों के बदलाव से नहीं, बल्कि संस्थागत सुधारों से स्थायी परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन पूरी तरह लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण था। ऐसे में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया जाना चाहिए।

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने नौवीं क्लास की छात्राओं को साइकिलें बांटीं

नयी दिल्ली, एजेंसी । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को यहां पूर्वी विनोद नगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक समारोह में सरकारी स्कूलों की नौवीं कक्षा की छात्राओं को साइकिलें वितरित कीं। गुप्ता के साथ शिक्षा मंत्री आशीष सूद और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा भी थे। मुख्यमंत्री ने कहा, हमें दिल्ली के सरकारी स्कूलों की कक्षा नौवीं की छात्राओं को विद्या वाहिनी साइकिलें प्रदान करते हुए खुशी हो रही है। यह साइकिल सम्मान का माध्यम बनेगी और उन्हें सुरक्षित रूप से स्कूलों तक आने-जाने में मदद करेगी। आज 'विद्या वाहिनी योजना' के तहत 3,000 से अधिक बेटियों को साइकिलें सौंपकर अपार संतोष की अनुभूति हुई। आप सभी खूब मन लगाकर पढ़ें, अपने सपनों को साकार करें, दिल्ली, अपने परिवार और देश का नाम रोशन करें। आप सभी को ढेरों बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अधिकारियों के मुताबिक, इस साल बजट में घोषित योजना के पहले चरण में 3,000 साइकिलें बांटी गईं। अगले महीने चरणबद्ध तरीके से दिल्ली भर में स्कूली छात्राओं को कुल 1.40 लाख साइकिलें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य स्कूल आने-जाने को आसान बनाना, नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहित करना और लड़कियों को अधिक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनने में मदद करना है।

उमर खालिद की जमानत पर फैसला फिलहाल

टला, हाई कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

नयी दिल्ली, एजेंसी । दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगों से जुड़े मामले के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने मामले में नोटिस जारी करते हुए दिल्ली पुलिस को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। खालिद के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद यह उसकी तीसरी जमानत याचिका है और उसने मामले में अंतरिम जमानत का भी अनुरोध किया है। पीठ ने कहा कि वह खालिद की याचिका पर 27 अगस्त को सुनवाई करेगी। इसी दिन सह-आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। खालिद ने अधीनस्थ अदालत के चार जुलाई के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने कहा कि अधीनस्थ अदालत ने इसी आदेश में इमाम की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी इसलिए पीठ दोनों मामलों पर एक साथ सुनवाई कर सकती है। सितंबर 2020 में गिरफ्तार खालिद के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उस पर फरवरी 2020 के दंगों के मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल होने का आरोप है। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 और राष्ट्रीय नागरिक पंजी के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़की थी। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा उस कथित व्यापक साजिश के मामले की जांच कर रही है जिसमें शरजील इमाम और खालिद सैफी तथा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत कई लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। अधीनस्थ अदालत ने चार जुलाई को उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उसके पास सुप्रीम कोर्ट के पांच जनवरी के आदेश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और इसलिए वह न तो याचिका पर विचार कर सकती है और न ही उन्हें राहत दे सकती है।

शहर समता विचार मंच द्वारा

ऑनलाइन काव्य गोष्ठी गुरु पूर्णिमा

के उपलक्ष्य में सफलतापूर्वक सम्पन्न



अनीता दुबे, अर्चना झा, पूनम पांडे, मीना कुमारी, आशा जाकड़ रचनाकार बहनों ने सुंदर रचनाओं की प्रस्तुति द्वारा आयोजन में चार चांद लगा दिये। धन्यवाद ज्ञापन उमा मिश्रा प्रीति ने किया।

राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज

आप भारत का अतीत हैं, भविष्य से संभलकर निपटें

नई दिल्ली, एजेंसी । पेपर लीक कानून में संशोधन और छात्र प्रदर्शनकारियों पर हो रही पुलिसिया कार्रवाई को लेकर देश की राजनीति गरमा गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वे भारत का अतीत हैं और उन्हें देश के भविष्य (Gen Z) के साथ संभलकर व्यवहार करना चाहिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार छात्र प्रदर्शनकारियों को धमकाने, उन पर एफआईआर दर्ज करने और उनके सोशल मीडिया



अकाउंट्स को ब्लॉक कराने का काम कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार की

कार्रवाई पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने लिखा, पीएम मोदी और अमित शाह — आप जेन—जी को डराकर चुप नहीं करा सकते। पहले आपने उनकी

हड्डियां तोड़ीं। अब आप उन पर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हटा रहे हैं। राहुल गांधी का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो संदेश के ठीक बाद आया है, जिसे पीएम ने इंस्टाग्राम पर जारी किया था। दरअसल, संसद ने श्लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को पास कर दिया है। यह नया कानून 2024 के एंटी-पेपर लीक कानून को और ज्यादा सख्त बनाता है, जिसमें दोषी पाए जाने वालों के लिए कड़े दंड का प्रावधान शामिल किया गया है।

कोडीन कफ सिरप केस में जज को प्रभावित करने की कोशिश, खुद सुनवाई से हटे, इतिहास का काला दिन बताया

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोडीन कफ सिरप मामले में लंबित जमानत याचिकाओं की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश तक निजी तौर पर पहुंचने की कोशिश पर कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने इसे न्यायालय के इतिहास का श्काला दिनश् बताते हुए कहा कि लंबित मामले को प्रभावित करने का कोई भी प्रयास न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। इसके बाद उन्होंने 74 जमानत याचिकाओं की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया और मामलों को नई पीठ के गठन के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजने का आदेश दिया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोडीन कफ सिरप मामले से जुड़ी 74 जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही एकल पीठ के न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने खुद को इससे अलग कर लिया है। सुनवाई के दौरान उन्होंने बेहद कड़ी टिप्पणी की है। कहा कि लंबित मामले को प्रभावित करने या न्यायाधीश तक पहुंच बनाने का कोई भी प्रयास न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला है। उन्होंने इसे न्यायालय के इतिहास का काला दिन करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित मामलों की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया। न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने सभी मामलों को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष नई पीठ के गठन के लिए भेजने का



आदेश दिया। यह आदेश उन्होंने भोला प्रसाद की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिया है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि न्याय व्यवस्था की पूरी नींव इस विश्वास पर टिकी है कि न्याय निष्पक्ष, निर्भीक और किसी भी बाहरी प्रभाव से मुक्त होकर दिया जाता है। यदि कोई पक्षकार या उससे जुड़ा व्यक्ति न्यायाधीश तक पहुंचने या निजी तौर पर संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है तो यह न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता और कानून के शासन पर सीधा प्रहार है। अदालत ने कहा कि मामले की अंतिम सुनवाई पूरी हो चुकी थी। आदेश पारित किया जाना था। इसी दौरान संबंधित पक्षों की ओर से पीठासीन न्यायाधीश तक पहुंचने के प्रयास किए गए। ऐसे आचरण को नजरअंदाज किया गया तो इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर लोगों का विश्वास कमजोर होगा। यह संदेश जाएगा कि न्यायिक आदेशों को प्रभावित किया जा सकता है।

हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे हालात में भले ही फैसला पूरी तरह कानूनी और तथ्यों पर आधारित होता, फिर भी उसके बारे में यह संदेह पैदा होता कि निर्णय बाहरी प्रभाव का परिणाम है। कोर्ट ने कहा कि किसी लंबित मामले में न्यायाधीश से न्यायालय के बाहर संपर्क स्थापित करने का प्रयास न्यायिक मर्यादा, अधिवक्ता आचार संहिता और सांविधानिक मूल्यों के विपरीत है। ऐसे व्यवहार को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने आदेश दिया कि सभी जमानत याचिकाएं और उससे संबद्ध अन्य मामलों को किसी अन्य पीठ के समक्ष 7 अगस्त 2026 को सूचीबद्ध किया जाए।

मुख्य बातें और घटनाक्रम

मामला: एक याचिका और कई जमानत अर्जियों की सुनवाई के दौरान पक्षकारों की ओर से अदालत के बाहर जज से निजी तौर पर संपर्क करने की कोशिश की गई।

अदालत की प्रतिक्रिया: इस पर गहरी नाराजगी जताते हुए न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने खुद को उन मामलों की सुनवाई से अलग कर लिया।

कड़ी टिप्पणी: उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के कृत्य न्यायिक स्वतंत्रता के लिए बड़ा खतरा हैं। मामलों की फाइलों को नए सिरे से आवंटन के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया।

कोडीन कफ सिरप मामले में कई जिलों में दर्ज हैं प्राथमिकी कोडीन कफ सिरप मामले में कई जिलों में प्राथमिकी दर्ज हैं। जमानत के लिए कई याचिकाएं कोर्ट में दाखिल हैं। मुख्य सरगना शुभम जायसवाल फरार चल रहा है। उसके पिता भोला प्रसाद की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकलपीठ सुनवाई कर रही थी। बता दें कि शुभम जायसवाल और अन्य आरोपियों की एफआईआर रद्द करने की याचिकाएं दिसंबर 2025 में खारिज हो चुकी हैं। हाई प्रोफाइल मामले में अब तक 50 से अधिक लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एसटीएफ और ईडी पूरे सिंडिकेट, फंड्री दस्तावेजों, वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है।

नैनी में किशोर के निजी अंग में चलाया कंफ्रेसर, चली गई जान, आरोपी गिरफ्तार

प्रयागराज। औद्योगिक क्षेत्र थाना स्थित एक राइस मिल में नाइट शिफ्ट के दौरान किसी बात पर हुए विवाद के बाद युवक ने किशोर के शरीर में कंफ्रेसर पाइप का इस्तेमाल कर मशीन चला दी। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। औद्योगिक क्षेत्र पुलिस के अनुसार एसपी सारटेक्स राइस मिल में काम कर एक किशोर के साथ मारपीट में घायल होने की सूचना मिली थी। वहां पहुंचने पर फोरमैन बंटी सिंह ने जानकारी दी कि मिल के अंदर काम करने वाले विशाल (18) पुत्र वसीम अहमद निवासी वार्ड नंबर दस, धूरा टांडा अरा, बरेली धौरा उप्र और अंश कुमार (15) पुत्र भीम निवासी ग्राम हरगढ़ मेजा की नाइट शिफ्ट थी। दोनों एक साथ काम कर रहे थे। इस दौरान उनके बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इस पर विशाल ने अंश के मलद्वार में राइस मिल में इस्तेमाल किए जाने वाली कंफ्रेसर पाइप डाल कर मशीन चालू कर दी। किशोर किसी तरह वहां से भागा और कंपनी के कर्मचारी मोहम्मद अमीर के पास पहुंचा। घटनाक्रम बताते हुए अपनी तबीयत खराब होने की बात कही। कर्मचारी उसे निजी अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर उसे स्वरूप रानी नेहरु चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। किशोर की मौत की सूचना पर एसपी करछना सुनील कुमार सिंह, औद्योगिक क्षेत्र थाने के एसओ कमलेश कुमार, नैनी इंस्पेक्टर बृज किशोर गौतम ने राइस मिल पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया। वहां लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखे और नाइट शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों से पूछताछ की। मृत किशोर के गांव की प्रधान अनीता देवी ने बताया कि उसका पिता मानसिक रूप से कमजोर है। उसकी मां उसे लेकर नैनी में रहती है।

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य के कई थाने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के बजाय व्यावसायिक गतिविधियों के केंद्र बनते जा रहे हैं। कोर्ट ने रसड़ा थाने के मामले में डीजीपी और अपर मुख्य सचिव (गृह) को जांच कर दोषी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र पुलिस विभाग में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार और पुलिसकर्मियों की व्यावसायिक गतिविधियों पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि राज्य के पुलिस थाने अब कानून-व्यवस्था बनाए रखने के बजाय व्यावसायिक गतिविधियों के अड्डे बनते जा रहे हैं।

इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने डीजीपी और अपर मुख्य सचिव (गृह) को रसड़ा थाने की जांच कर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ

हाईकोर्ट ने कहा- व्यावसायिक गतिविधियों का अड्डा बने हैं थाने, डीजीपी करें जांच

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य के कई थाने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के बजाय व्यावसायिक गतिविधियों के केंद्र बनते जा रहे हैं। कोर्ट ने रसड़ा थाने के मामले में डीजीपी और अपर मुख्य सचिव (गृह) को जांच कर दोषी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र पुलिस विभाग में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार और पुलिसकर्मियों की व्यावसायिक गतिविधियों पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि राज्य के पुलिस थाने अब कानून-व्यवस्था बनाए रखने के बजाय व्यावसायिक गतिविधियों के अड्डे बनते जा रहे हैं।

इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने डीजीपी और अपर मुख्य सचिव (गृह) को रसड़ा थाने की जांच कर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ



अधिकारी (एसआरटीओ), बलिया की ओर से उनके ट्रक को ब्लैक कलिस्ट कर उसके हस्तांतरण पर रोक लगाने के खिलाफ याचिका दायर कर चुनौती दी थी।

सुनवाई के दौरान सामने आया कि रसड़ा थाने में तैनात कांस्टेबल संतोष कुमार ने अपने जीपीएफ से धन निकालकर याची हरेंद्र यादव के नाम पर

एक ट्रक खरीदा था। दोनों के बीच ट्रांसपोर्ट का कारोबार शुरू किया गया लेकिन बाद में व्यावसायिक विवाद होने पर पुलिस विभाग के प्रभाव का इस्तेमाल किया गया। आरोप

व्यावसायिक गतिविधियों का अड्डा बने थाने, डीजीपी करें जांच इलाहाबाद हाईकोर्ट

है कि रसड़ा थाने के उपनिरीक्षक शिव मूर्ति तिवारी ने एसआरटीओ को रिपोर्ट भेजी, जिसके आधार पर ट्रक को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और उसके हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई।

यही स्थिति रही तो कानून-व्यवस्था बनाए रखना कठिन हो जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा रसड़ा थाना ही व्यावसायिक गतिविधियों में संलिप्त है।

अदालत ने रजिस्ट्रार (अनुपालन) को आदेश की प्रति 48 घंटे के भीतर संबंधित अधिकारियों को भेजने तथा डीजीपी को दस दिनों के भीतर की गई कार्रवाई का शपथ-पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है।

प्रयागराज। प्रयागराज में मेट्रो रेल परियोजना को जमीन पर उतारने की तैयारी तेज हो गई है। करीब 12 हजार करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (वक्त) 14 अगस्त तक तैयार करने का लक्ष्य है। सब कुछ तय समय पर हुआ तो दिसंबर तक परियोजना का शिलान्यास हो सकता है। प्रस्तावित मेट्रो एयरपोर्ट को झूंसी और फाफामऊ को नैनी से जोड़ेगी। दो कॉरिडोर में 40 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जबकि परेड मैदान में इंटरचेंज जंक्शन बनाया जाएगा।



तक इस परियोजना का शिलान्यास किया जा सकता है।

एयरपोर्ट को झूंसी और फाफामऊ को नैनी से जोड़ेगी मेट्रो ट्रेन

प्रस्ताव के अनुसार मेट्रो ट्रेन प्रयागराज एयरपोर्ट को झूंसी और फाफामऊ को नैनी से जोड़ेगी। परेड मैदान पर इंटरचेंज जंक्शन बनेगा और दो कॉरिडोर के तहत कुल 40 स्टेशन बनाए जाएंगे। डिपो बनाने के लिए झूंसी व नैनी में 20—20 हेक्टेयर जमीन विहित की गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर

का शिलान्यास किया जा सकता है।

एयरपोर्ट को झूंसी और फाफामऊ को नैनी से जोड़ेगी मेट्रो ट्रेन

प्रस्ताव के अनुसार मेट्रो ट्रेन प्रयागराज एयरपोर्ट को झूंसी और फाफामऊ को नैनी से जोड़ेगी। परेड मैदान पर इंटरचेंज जंक्शन बनेगा और दो कॉरिडोर के तहत कुल 40 स्टेशन बनाए जाएंगे। डिपो बनाने के लिए झूंसी व नैनी में 20—20 हेक्टेयर जमीन विहित की गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर

का शिलान्यास किया जा सकता है।

प्रयागराज। प्रयागराज में मेट्रो रेल परियोजना को जमीन पर उतारने की तैयारी तेज हो गई है। करीब 12 हजार करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (वक्त) 14 अगस्त तक तैयार करने का लक्ष्य है। सब कुछ तय समय पर हुआ तो दिसंबर तक परियोजना का शिलान्यास हो सकता है। प्रस्तावित मेट्रो एयरपोर्ट को झूंसी और फाफामऊ को नैनी से जोड़ेगी। दो कॉरिडोर में 40 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जबकि परेड मैदान में इंटरचेंज जंक्शन बनाया जाएगा।

प्रयागराज। प्रयागराज में मेट्रो रेल परियोजना को जमीन पर उतारने की तैयारी तेज हो गई है। करीब 12 हजार करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (वक्त) 14 अगस्त तक तैयार करने का लक्ष्य है। सब कुछ तय समय पर हुआ तो दिसंबर तक परियोजना का शिलान्यास हो सकता है। प्रस्तावित मेट्रो एयरपोर्ट को झूंसी और फाफामऊ को नैनी से जोड़ेगी। दो कॉरिडोर में 40 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जबकि परेड मैदान में इंटरचेंज जंक्शन बनाया जाएगा।

इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने डीजीपी और अपर मुख्य सचिव (गृह) को रसड़ा थाने की जांच कर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ

प्रयागराज। प्रयागराज में मेट्रो रेल परियोजना को जमीन पर उतारने की तैयारी तेज हो गई है। करीब 12 हजार करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (वक्त) 14 अगस्त तक तैयार करने का लक्ष्य है। सब कुछ तय समय पर हुआ तो दिसंबर तक परियोजना का शिलान्यास हो सकता है। प्रस्तावित मेट्रो एयरपोर्ट को झूंसी और फाफामऊ को नैनी से जोड़ेगी। दो कॉरिडोर में 40 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जबकि परेड मैदान में इंटरचेंज जंक्शन बनाया जाएगा।

पर्यटन मंत्री बोले: 39.10 करोड़ की 25 परियोजनाओं से बदलेगी मंडल के तीर्थ, तालाब और मंदिरों की तस्वीर

प्रयागराज। प्रयागराज मंडल में धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास के लिए 39.10 करोड़ रुपये की 25 परियोजनाओं पर काम तेज किया गया है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने समीक्षा कर अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य के निर्देश दिए।

प्रयागराज मंडल के धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को नई पहचान देने की तैयारी तेज हो गई है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने शुक्रवार को पर्यटन, संस्कृति और धर्मार्थ कार्य विभाग की करीब 39.10 करोड़ रुपये लागत वाली 25 परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से काम पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रयागराज की 15, प्रतापगढ़ की छह और फतेहपुर की चार परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि पर्यटन परियोजनाएं केवल निर्माण कार्य नहीं हैं, बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और श्रद्धालुओं व पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का माध्यम हैं। उन्होंने एक करोड़ रुपये तक की परियोजनाएं नवंबर तक, 1.5 करोड़ रुपये तक की छह माह और दो करोड़ रुपये तक की परियोजनाएं नौ माह में पूरी करने के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात ने भी विभागों और कार्यदायी संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया।

प्रयागराज में संसारी माता धाम, महावीरन धाम, मां ज्वालामुखी मंदिर, श्री नर्मदेश्वर शिव मंदिर और संत रविदास मंदिर के विकास के साथ करीब आठ करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले शपरंपराश वन स्टॉप सेंटर फॉर टूरिज्म एंड कल्चर की भी समीक्षा हुई। यह केंद्र पर्यटन, संस्कृति और आगंतुक सुविधाओं का एकीकृत केंद्र बनेगा। संस्कृति विभाग की समीक्षा में श्रृंगवेरपुर के निषादराज गुह सांस्कृतिक केंद्र, मंझनपुर के कौशाम्बी संग्रहालय, जहानाबाद और खागा के रामलीला मैदान समेत कई निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। धर्मार्थ कार्य विभाग की करीब 23.08 करोड़ रुपये लागत की भजन संध्या स्थल परियोजना और विभिन्न मंदिरों के संरक्षण एवं विकास प्रस्तावों की भी समीक्षा की गई।

सामूहिक दुष्कर्म में पहरा देने या पीड़िता को पकड़ने वाला भी मुख्य अपराधी के बराबर दोषी, सजा बरकरार

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कई लोग साझा आपराधिक मंशा (कॉमन इंटेंशन) के तहत दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते हैं, तो केवल दुष्कर्म करने वाला ही नहीं, बल्कि पीड़िता को पकड़ने, पहरा देने या अपराध में सहयोग करने वाला प्रत्येक आरोपी भी समान रूप से दोषी माना जाएगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि साझा आपराधिक मंशा के तहत कार्य करने पर प्रत्येक आरोपी पर दुष्कर्म का समान दायित्व बनता है, भले ही उसने स्वयं दुष्कर्म न किया हो। पीड़िता को पकड़ने और पहरा देने वाला व्यक्ति भी मुख्य अपराधी के बराबर दोषी होता है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में दोषी सुभाष सिंह व शेर सिंह की अपील खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति संतोष राय की एकलपीठ ने दिया है।

रामपुर निवासी अपीलकर्ताओं पर थाना टांडा में दुष्कर्म के आरोप में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। आरोप था कि मार्च 1984 को पीड़िता और उसकी भतीजी गांव के जंगल में सूखी पतियों बौनने गई थीं। वहां पहले से मौजूद पांच आरोपियों ने दोनों महिलाओं को घेर लिया। दो आरोपियों ने महिलाओं को पकड़ लिया। दो अन्य ने उनके साथ दुष्कर्म किया और एक आरोपी पहरा देता रहा। पीड़िताओं के शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपी फरार हो गए। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि उन्होंने स्वयं दुष्कर्म नहीं किया। इसलिए उन्हें इस अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह भी कहा गया कि एक आरोपी केवल पहरा दे रहा था। इसलिए उस पर दुष्कर्म की धारा लागू नहीं होती। हाईकोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 साझा आपराधिक मंशा के सिद्धांत पर आधारित है। यदि कोई व्यक्ति अपराध को सफल बनाने के उद्देश्य से सक्रिय सहयोग करता है, चाहे वह पीड़िता को पकड़ना हो या पहरा देना तो वह भी मुख्य अपराधियों के समान उत्तरदायी होगा। साझा मंशा के तहत किए गए अपराध में प्रत्येक सहभागी पूरे अपराध के लिए समान रूप से जिम्मेदार होता है। अन्य तथ्यों पर विचार करते हुए कोर्ट ने दोषसिद्धि के साथ ही पूर्व में दी गई सजा को बरकरार रखा।

तहसील भवन का बाज्रा गिरा, लोग सहमे

प्रयागराज। तहसील मुख्यालय बारा की जर्जर बिल्डिंग का बाज्रा बृहस्पतिवार की सुबह गिर गया। उस समय तहसील कार्यालय बंद होने के कारण दुर्घटना टल गई। भवन निर्माण के बाद मरम्मत कार्य न होने के कारण अधिकारियों और कर्मचारियों के आवास पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं और उनके खिड़की, दरवाजे तक गायब हो गए हैं। तहसील मुख्यालय का भवन भी जर्जर हालत में हो गया है। कुछ दिन पहले एसडीएम न्यायालय के किनारे का बाज्रा गिरा था, कोई अनहोनी नहीं हुई थी। सुबह एसडीएम कार्यालय के सामने का बाज्रा गिर गया। लोगों ने बताया कि अचानक बाज्रा गिरने से आसपास के लोग डर गए थे। संयोग है कि उस समय वहां कोई नहीं था अन्यथा बड़ी घटना हो सकती थी। इस संबंध में तहसीलदार बारा अनिल कुमार पाठक ने कहा कि तहसील भवन के मरम्मत का कार्य चल रहा है। उसे गिरा दिया गया है, मरम्मत कराई जाएगी।

दीपोत्सव में सामाजिक समरसता का दिया संदेश

प्रयागराज। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज यमुनापार की ओर से संचालित समरसता संकल्प अभियान के अंतर्गत बुधवार को नारीबारी मंडल में श्री सर्वेश्वर हनुमान मंदिर और शिव मंदिर परिसर में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। दीप प्रज्ज्वलन के माध्यम से सामाजिक समरसता, समानता और सद्भाव का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम में भाजपा जिला महामंत्री रत्नाकर सिंह पटेल हनुमान मंदिर में मुख्य अतिथि और जिला मीडिया प्रभारी दिलीप कुमार चतुर्वेदी शिव मंदिर के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने पुजारी रमेश दास जी महाराज को अंगवस्त्र एवं माल्यार्पण कर सम्मानित किया। इसके बाद लोगों ने दीप प्रज्ज्वलित कर संत गुरु रविदास के आदर्शों के अनुरूप समरस समाज के निर्माण का संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष आशीष पाल ने की। इस अवसर पर मंडल प्रभारी बड़ोछर वीरेन्द्र शुक्ला, धर्मराज पाल, प्रदीप मिश्र, राजेश केसरवानी, नीरज त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।

सम्पादकीय.....

पंजाब कांग्रेस बुरी तरह बिखराव की शिकार

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आलाकामान ने पंजाब के चुनावी कुरुक्षेत्र में उतरने से पहले कांग्रेस को सुनियोजित, सुनिश्चित और सुसंगठित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कमेटियों का गठन किया, जिसमें अपने महारथियों और राजनीति में गहन तजुर्बा रखने वाले धुरंधर नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपीं, ताकि वे उन्हें खूबसूरत तरीके से सरअंजाम देकर कांग्रेस को पंजाब में सत्तासीन कर सकें और लोगों के जज्बात की तर्जुमानी करके पंजाब में शांति, समृद्धि और विकास की नीतियों को अमलीजामा पहना सकें। परंतु चंद रोज बाद पंजाब कांग्रेस के एक बड़े गुट ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया कि वह न तो प्रदेश प्रधान के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं और न ही उसका समर्थन करेंगे। इस खबर ने पंजाब के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को मायूस ही नहीं किया, बल्कि उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया। इससे स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस बुरी तरह बिखराव की शिकार है। हकीकत में पंजाब कांग्रेस के लंबे इतिहास में पहली बार कांग्रेस के एक बड़े गुट ने आलाकमान को पार्टी हित में सुझाव दिया है, चुनौती दी है या बगावत की है। जब पिछले साढ़े 4 वर्षों से प्रदेश प्रधान को सहयोग दे रहे थे तो फिर चुनावों के नजदीक उसको बदलने के लिए आलाकमान पर दबाव क्यों डाला जाने लगा? यह मंसूबा समझ से परे है, संशयपूर्ण है और दाल में कुछ काला तो जरूर लगता है। इतिहास साक्षी है कि सभी राजनीतिक दलों के आलाकमान ही सर्वोपरि होते हैं और प्रदेशों में नियुक्तियां भी उनके अधिकार क्षेत्र में आती हैं। कई बार वे प्रदेशों के प्रतिष्ठित नेताओं से सलाह–मशविरा कर लेते हैं और कई बार अपनी रिपोर्ट के आधार पर नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपते हैं। जिन्हें बिना किसी किंतु–परंतु के प्रदेश का पार्टी नेतृत्व सार्थ स्वीकार कर लेता है। यही परम्परा पिछले कई वर्षों से चली आ रही है और भविष्य में भी ऐसे ही चलती रहेगी। कांग्रेस भारत की 141 वर्ष पुरानी आलीशान और गौरवमयी इतिहास की पार्टी रही है और उसका शीर्ष नेतृत्व ही प्रदेशों से संबंधित फैसला लेते आया है। ये फैसले राजनीतिक तौर पर फलदायक रहें या नुकसानदायक, यह चर्चा का विषय हो सकता है। एक गुट के दबाव में यदि आलाकमान घुटनों पर आ जाती है तो फिर दूसरे प्रदेशों में भी ऐसे बगावती सुरु उठने लगेंगे, जो उनके अधिकार क्षेत्र को ही चुनौती होगी। यदि कोई मांग उचित भी हो तो उसका समाधान करने का तरीका युक्तिसंगत, समयानुकूल और हालाते हाजरा की जरुरीयात के मुताबिक हो। समस्या को लटकाना भी समस्या का समाधान नहीं होता। कांग्रेस पार्टी के प्रादेशिक संगठनों में यदि गुटबाजी है तो आलाकमान भी अपनी कमियों, कमजोरियों और गुटों को प्रोत्साहित करने की गैर–मामूली जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। पंडित नेहरू और सरदार पटेल के समय भी 2 गुट थे, परंतु दोनों के मुख्य उद्देश्य बड़े सकारात्मक, सृजनात्मक और रचनात्मक थे। वह पार्टी के हितों से ऊपर राष्ट्र के हितों को ही सर्वोच्च मानते थे। एक ने समूचे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोया और दूसरे ने हर क्षेत्र में विकास की बुनियाद रखी। वर्तमान समय में गुटबाजी निजी स्वार्थों तक सीमित होती जा रही है जो अति विनाशकारी साबित हो रही है। कांग्रेस आलाकमान पहले ही जल्दबाजी, गुटबाजी और खुशामदियों के सलाह–मशविरे से असम गंवा बेठी है। हरियाणा में जीतती–जीतती पराजित हो गई और पंजाब में जिस फैसले को मास्टर स्ट्रोक कहते थे, वही कांग्रेस को ले ढ़ूबा और पार्टी विधानसभा में 18 सीटों तक सीमित रह गई। यह जानते हुए भी कि युद्ध के मैदान में छोड़े नहीं बदले जाते, फिर भी उन्होंने चुनाव से कुछ नहीने पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदल कर हिमालय से भी बड़ी गलती की। हकीकत में लोकप्रिय नेता को बदलने का न समय ठीक था और न ही फैसला, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा।राजनीति शतरंज के मोहरों की तरह शह और मार का खेल होता है। मामूली गलती से कई बार बादशाह भी मारा जाता है। कांग्रेस के ठीक समय पर ठीक फैसले न लेने से तमिलनाडु, बंगाल, यूपी. और बिहार हाथ से निकल गए और आज तक कांग्रेस के इन प्रदेशों में पांव नहीं जमे। हकीकत में कांग्रेस का सरचनात्मक और कार्यात्मक प्रकोष्ठ अति कमजोर हो चुके हैं। प्रदेशों के संगठनात्मक ढांचे भी शिथिल हो रहे हैं। देश में 90 करोड़ मतदाताओं में आधी महिलाएं हैं, परंतु महिला कांग्रेस का प्रभाव भी फीका पड़ रहा है। युवा कांग्रेस, कांग्रेस का एक मकबूल और शक्तिशाली फोर प्रंट था, जो अब कई छोटे–छोटे संकीर्ण गुटों में बंटा हुआ है। इन पर भी प्रभावशाली विधायकों और मंत्रियों का नियंत्रण है। इंटक कांग्रेस का एक बड़ा ही शक्तिशाली विंग था, जिसमें लाखों औद्योगिक, व्यापारिक और कृषि क्षेत्र से संबंधित मजदूर होते थे जो अब अपना वर्चस्व खो चुका है। इसी तरह सेवा दल, जिसके मुखिया कभी पंडित नेहरू थे, आज थोड़े से लोगों के हाथों में सिमट कर रह गया है। जबकि आर.एस.एस. की भारत में करीब 80 हजार के लगभग शाखाएं हैं, जो हर समय सक्रिय रहते हैं।

सर्वमित्रा सुरजन
केंद्र सरकार में नए शिक्षा मंत्री बने प्रहलाद जोशी को काम संभाले अभी चार दिन भी नहीं बीते कि उन पर विवाद खड़े हो गए हैं। संसद में उनके नाम पर हंगामा हो गया। दरअसल मंगलवार को प्रियंका गांे ने पेपर लीक विरोधी विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री ने एक नए शिक्षामंत्री को नियुक्त किया है। एक ऐसे व्यक्ति को जिन्हेंगे गर्भवती महिला के साथ बलात्कार के दोषियों की रिहाई पर सहमति और खुशी भी जताई थी। देश के करोड़ों लोगों को प्रधानमंत्री ने क्या संदेश दिया है। इस टिप्पणी के बाद सदन में हंगामा खड़ा हो गया। भाजपा सांसद इसका विरोध करने लगे और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे चरित्र हनन बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई थी और टिप्पणी हटाने की मांग की थी, जिसके बाद इस टिप्पणी को कार्यवाही से हटा दिया गया। विपक्ष के सांसद कुछ भी कहें तो सत्तापक्ष में बैठे लोग उस पर ऐतराज जताते ही हैं यही इस सरकार में चलन हो गया है। बुधवार को तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को यहां तक कहना पड़ा कि अगर केवल भाजपा के लोगों को बोलने की इजाजत है तो फिर मैं बैठ ही जाता हूं। क्योंकि वे जब भी कुछ कहते सत्ता पक्ष उन्हें टोकने लगता। लेकिन प्रियंका गांधी की टिप्पणी पर भाजपा के लोगों ने क्यों हंगामा किया, किरण रिजिजू को यह किस तरह से चरित्र हनन लगा, यह भाजपा को बता देना चाहिए। गौरतलब है कि गुजरात दंगों में

बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था और उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार डाला गया था, जिसके बाद लंबी कानूनी लड़ाई बिलकिस बानो ने लड़ी थी और जनवरी 2008 में उनके 11 दोषियों को सजा सुनाई गई। लेकिन 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत 11 दोषियों को रिहा किया था। तब इन बलात्कारियों का फूल–माला पहना कर स्वागत हुआ था, भाजपा और संघ के कई लोगों ने इस फैसले को सही ठहराया था। प्रहलाद जोशी भी उन्ही में से एक थे। एनडीटीवी ने उनसे सवाल पूछा था और उनका जवाब रिकार्ड में है। सोशल मीडिया पर यह उपलब्ध है। हालांकि 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को गलत बताया और सारे दोषी फिर जेल में है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या अब प्रहलाद जोशी को अपना चार साल पुराना बयान सही नहीं लग रहा है। अगर ऐसा है, तो वे बलात्कारियों की रिहाई के समर्थन में बयान देने पर माफी क्यों नहीं मांग लेते। और अगर उन्हें अपना पुराना बयान सही लगता है तो फिर प्रियंका गांधी की टिप्पणी तौर पर इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। किरण रिजिजू चरित्र हनन की बात किसलिए कर रहे हैं, क्या बलात्कार पीड़िता के समर्थन में खड़े होना भाजपा की नजर में चरित्र हनन है। असल बात यह है कि अस्तित्वत और नैतिकता के दिखावे के बीच भाजपा नेता फंस रहे हैं। प्रियंका गांधी के जिस बयान को संसदीय कार्यवाही से हटा दिया

गया, उसी बयान को राहुल गांधी ने बाहर आकर पत्रकारों के सामने कहा। राहुल ने लिखा भी कि बलात्कारियों का बचाव करने वाले व्यक्ति से ज्यादा घटिया और कोई नहीं हो सकता। प्रहलाद जोशी हमारे शिक्षा तंत्र और उसमें पढ़ने वाले हर छात्र का अपमान हैं। जिन संस्थानों की देखरेख अब वे करते हैं, उनमें करोड़ों युवतियां पढ़ती हैं। भारत की महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी के नए शिक्षा मंत्री को कभी स्वीकार नहीं करेंगी। विपक्षी सांसदों की ये टिप्पणियां बता रही हैं कि प्रहलाद जोशी के लिए भी शिक्षा मंत्रालय संभालना आसान नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से धर्मप्र प्रधान को मंत्रालय से हटाकर नरेन्द्र मोदी ने अपने लिए थोड़ी राहत का इंतजाम किया था, लेकिन अब प्रहलाद जोशी के कारण और बड़ी मुसीबत में मोदी फंस सकते हैं। क्योंकि सरकार का रवैया अब भी घृणा और तिरस्कार दिखाने का ही है।हम जानते हैं कि जंतर–मंतर पर सरकार के विरोध में एक महीने से लंबा आंदोलन चला, जो शिक्षा मंत्री धर्मप्र प्रधान के इस्तीफे के साथ खत्म हुआ। नरेन्द्र मोदी ने शुरु से अपनी छवि एक सख्त प्रशासक के तौर पर बनाई थी, उनके समर्थकों ने भी 56 इंच की छाती, दुश्मनों को लाल आंखें दिखाना जैसी बातों को खूब बढ़ाकर एक गुब्बारा सा बना लिया था, जिसके भीतर कठोर, मजबूत फैसले लेने वाले प्रभामंडरी दिखाई देते थे। लेकिन नयी पीढ़ी के निडर रवये और अपनी वाजिब मांगों के लिए डटकर खड़े रहने के कारण मोदी को झुकना पड़ा। मोदी झुके ही

जंतर–मंतर पर मोदी की युवाओं के लिए कहानी लड़खड़ा गई!

के रवींद्रन
केंन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आखिरकार नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है। मौजूदा सरकार में मंत्री और मोदी हालात के लिए इससे अच्छा सम्मानजनक रास्ता नहीं हो सकता था। धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को निजी दुश्मनी से चलाया जा रहा अभियान बताने का कोई ठोस आधार नहीं है। न तो कॉर्पोरेट जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके और न ही जंतर–मंतर पर जमा हुए युवा प्रदर्शनकारियों ने मंत्री के खिलाफ किसी निजी शिकायत को अपनी लामबंदी के केन्द्र में रखा है। उनका मामला राजनीतिक और संस्थागत थारु प्रधान एक ऐसे मंत्रालय के मुखिया थे जिसकी देखरेख में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की साख बुरी तरह से गिर गई है, और वे चाहते हैं कि सर्वोच्च स्तर पर जिम्मेदारी तय हो। यह फर्क मायने रखता है। सरकारें अक्सर असहज आंदोलनों का जवाब उनका नेतृत्व करने वालों के मकसद, जुड़ाव या शख्सियत पर सवाल उठाकर देती हैं। ऐसे तरीके कुछ समय के लिए ध्यान भटका सकते हैं, लेकिन वे इस मुख्य आरोप का जवाब नहीं दे सकते कि जिंदगी तय करने वाली

परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को बार–बार पेपर लीक, परीक्षाओं को रद्द करने, गड़बड़ियों और प्रशासनिक अनिश्चितता का सामना करना पड़ा है। प्रदर्शनकारी सिर्फ दलालों, अधिकारियों या अपराधिाक बिचौलियों को सजा देने की मांग नहीं कर रहे थे। वे एक ऐसे शासन की संस्कृति को चुनौती दे रहे थे जिसमें जिम्मेदारी नीचे जाती दिखती है जबकि बड़े अधिकारी सुरक्षित रहते हैं। इस आंदोलन ने प्रधान को एक अकेले मंत्री से कहीं ज्यादा बना दिया। वह एक ऐसी परीक्षा मशीनरी का सार्वजनिक चेहरा बन गए हैं जिसे लाखों युवा भारतीय अब भरोसेमंद नहीं मानते। उनके इस्तीफे की मांग इसलिए नहीं की जा रही थी कि हर लीक का सीधा संबंध उनके ऑफिस से हो, बल्कि इसलिए की जा रही थी कि मंत्री की जिम्मेदारी का मतलब तभी होता है जब राजनीतिक आधिकारिकता के नतीजे प्रणाली की नाकामी के हों। सरकार के जवाब ने चुपचाप संकट की गंभीरता को मान लिया है। अधिकारियों को हटा दिया गया है, परीक्षा की जगह पर भर्ती के तरीकों पर फिर से विचार किया जा रहा है, पेपर लीक के खिलाफ कड़े कदम उठाने का वादा किया गया है और फास्ट–ट्रैक न्यायिक

प्रणाली की पेशकश की गई है। विरोध करने वाले प्रतिनिधियों के साथ बातचीत जारी है, जबकि केंद्र ने प्रधान से जुड़ी मांग पर और समय मांगा। ये किसी मामूली प्रदर्शन का सामना कर रहे प्रशासन की कार्रवाइयां नहीं थीं। ये सरकार की तरफ से एक ऐसे मुद्दे को नियंत्रित करने की कोशिश के संकेत थे जो परीक्षा प्रबंधन से आगे बढ़कर राजनीतिक वैधता के दायरे में आ गया है। प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी के दखल में भी वह दबाव दिखा। छात्रों से उनकी अपील और जवाबदेही का भरोसा तब आया जब आंदोलन बढ़ गया था, जंतर–मंतर पर टकराव तेज हो गया था और पुलिस कार्रवाई की तस्वीरें बड़े पैमाने पर फैल गई थीं। देरी ने उनके संदेश का असर कम कर दिया। जब तक प्रधानमंत्री ने बात की, तब तक झगड़ा सिर्फ एक लीक हुए पेपर का नहीं रह गया था। यह प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं, घटते नौकरी के मौकों, प्रशासनिक नाकामियों की वजह से सालों की तैयारी के खराब होने और इस सोच पर गुस्से का जमाव बन गया था कि आम उम्मीदवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है जबकि ताकतवर संस्थाएं जांच से बच जाती हैं। यहीं पर आंदोलन सीधे सरकार की बड़ी राजनीतिक शब्दावली से टकराया। मोदी ने लगातार

भारत की युवा आबादी को डेमोग्राफिक डिविडेंड और विकसित भारत के पीछे मुख्य ताकत के तौर पर पेश किया है। फिर भी डेमोग्राफिक डिविडेंड नाशों, आबादी के आकार या प्रेरक भाषणों से नहीं बनता है। यह भरोसेमंद शिक्षा, सही भर्ती, रोजगार बढ़ाने और इस भरोसे पर निर्भर करता है कि पैसे, हेरफेर या लीक हुए प्रश्नपत्र तक पहुंच से काबिलियत को हराया नहीं जाएगा।

प्रदर्शनकारी असल में सरकार को बता रहे थे कि यह सोशल कॉन्ट्रैक्ट टूट रहा है। एक उम्मीदवार जो सालों तक पढ़ता है और फिर देखता है कि उसकी परीक्षा रद्द हो गयी है, वह भारत के युवाओं के फायदे को एक मौके के तौर पर नहीं देखता। एक परिवार जो अपनी बचत कोचिंग पर खर्च करता है और फिर पेपर में गड़बड़ी के आरोपों का सामना करता है, वह संस्थागत सुधार को एक भाववाचक प्रशासनिक सवाल के तौर पर नहीं देखता। उनके लिए, नाकामी तुरंत वित्तीय रूप से नुकसानदेह और अक्सर बहुत बुरा होता है। आंदोलन के भौतिक फैलाव पर नजर खास तौर पर जरूरी है। यह किसी बड़ी विपक्षी पार्टी की संगठनात्मक मशीनरी से शुरु नहीं हुआ था। इसकी भाषा, इसके प्रतीक और एकत्रीकरण

मंत्रालय वापस लेकर उन्हें कपड़ा मंत्रालय दे दिया गया। फिर प्रकाश जावड़ेकर 5 जुलाई, 2016 से 30 मई, 2019 तक भारत सरकार के शिक्षा मंत्री के पद पर रहे। जावड़ेकर के कार्यकाल में ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की स्थापना हुई। इसका मकसद यह था कि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रवेश परीक्षाओं का संचालन एक ही संस्था के पास हो। लेकिन जिस तरह बार–बार नीट पेपर लीक हुए उसमें अब एनटीए घिरा हुआ है। जावड़ेकर के शिक्षा मंत्री रहते ही 2018 में सीबीएसई बोर्ड का पेपर लीक होने का विवाद खड़ा हुआ। इसके अलावा जिओ इंटीट्यूट को भारत के छह इंटीट्यूट ऑफ एमिनेंस में से एक बताया गया, जिस पर खूब विरोध हुआ। इंटीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस भारत सरकार और यूजीसी की तरफ से शुरु की गई एक योजना है, जिसके तहत 20 विश्व–स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थान तैयार किए जाते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के चुनिंदा सार्वजनिक और निजी संस्थानों को पूर्ण स्वायत्तता देकर वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट बनाना है। इस सूची में रिलायंस समूह के संस्थान को शामिल किया गया तो सवाल उठे। बहरहाल 2019 में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल मेंरमेश पोखरियाल निशंक को शिक्षा मंत्री बनाया गया। पोखरियाल के कार्यकाल में ही नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की घोषणा लागू हुई। लेकिन पोखरियाल के शिक्षा मंत्री रहने के दौरान सबसे बड़ी शिकायत यह रही कि जेएनयू बीएचयू दिल्ली विश्वविद्यालय और

हैदराबाद विश्वविद्यालय जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में कई महीनों तक कुलपतियों की नियुक्ति नहीं हुई। इसी तरह पटना, भुवनेश्वर, दिल्ली, इंदौर और मंडी इन पांच आईआईटी में भी पूर्णकालिक निदेशक नहीं नियुक्त किए गए। 7 जुलाई, 2021 को निशंक ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसकी वजह कोरोना के कारण स्वास्थ्य खराब होना कहा गया। फिर इस पद पर धर्मेप्र प्रधान आए और अब उन्हें किस तरह शिक्षा मंत्री का पद छोड़ना पड़ा, यह देखना देखा है। प्रहलाद जोशी तो शिक्षा मंत्री बनते ही विवादों में घिर गए हैं। मोदी सरकार के 12 सालों में शिक्षा मंत्रालय जैसे अहम विभाग का यह हथ्र देखकर देश के पहले शिक्षा मंत्री भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद याद आते हैं जिन्हें ग्यारह बरस तक इस मंत्रालय को संभाला। मौलाना आजाद ने आईआईटी की नींव रखी। खड़गपुर मेंदेश का पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी खुला, जिसके कारण तकनीकी शिक्षा की नयी राहें खुलीं। देश भर के विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के स्तर को सुधारने और उसकी देखरेख के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की स्थापना की। तकनीकी शिक्षा के उचित विकास के अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद गठित की। कला, साहित्य और संस्कृति के विकास और संरक्षण के लिए साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी जैसे राष्ट्रीय संस्थान बनाए।

म्यांमार सैन्य शासन का सशस्त्र विद्रोहियों को राजनीतिक

लोकतंत्र के लिए खतरनाक पक्षपाती रवैया
बुधवार को एक बार फिर संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई बार–बार स्थगित हुई, क्योंकि विपक्षी सांसदों के बयान सत्तापक्ष को मंजूर नहीं थे। हंगामे के बीच पेपर लीक विरोधी विधेयक तो लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया। किंतु लोकसभा में केवल सत्तापक्ष की ध्वनि के लिए जगह बची है, यह बात फिर स्थापित हो गई। 2024 में जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, भाजपा सरकार पहले से ज्यादा उद्देगित और असहज दिखने लगी है। राहुल गांधी ने कहा ही था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी में उनका सामना करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वे सदन में नहीं आते। अब शायद यही बात गृहमंत्री अमित शाह पर भी लागू हो जाएगी। राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में बोलते हुए छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए, जो सत्तापक्ष को इतने आपत्तिजनक लगे कि राहुल गांधी से माफी की मांग की जाने लगी। उनका भाषण पूरा नहीं हो पाया, कई बार उन्हें टोका गया। जिस पर राहुल गांधी को यहां तक कहना पड़ा कि अगर इस सदन में केवल भाजपा को बोलने का अधिकार है, तो फिर मैं चुप बैठ जाता हूं। हमेशा की तरह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला फिर निष्पक्ष रवैया दिखाने में नाकाम रहे। वे भले ही माननीय नेता प्रतिपक्ष कहकर अपनी बात रख रहे हों, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता के लिए मान उनके व्यवहार में नजर नहीं आया। यही बात सत्तापक्ष के सभी

सांसदों पर लागू होती है। खासकर संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजीजू पर, जिनका एकमात्र काम इस समय मोदी–शाह का बचाव करना नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने पेपर लीक आंदोलन में उतरे छात्रों पर गोलियां चलाने के लिए अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। जिस पर सत्तापक्ष भड़क उठा। किरण रिजीजू ने कहा कि इस बात के सबूत दीजिए, अगर नहीं दे सकते तो फिर ऐसा कहना ठीक नहीं है, आप माफी मांगिए। रिजीजू ने यह भी कहा कि ऐसे तो मैं भी कह सकता हूं कि राहुल गांधी ने किसी का मर्द किया है। क्या ऐसा कहना ठीक होगा। बात सही है कि सदन में किसी का भी नाम लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन राहुल गांी किसी की भी बात नहीं कर रहे थे, वे बाकायदा गृहमंत्री अमित शाह की बात कर रहे थे, जिनके अधीन पुलिस प्रशासन आता है, जिनके जिम्मे देश की आंतरिक सुरक्षा का दायित्व है। जंतर–मंतर पर छात्रों पर लाठी और आंसू गैस के गोले के अलावा पैंलेट गन से वार किया गया, जिसमें कुछ लोगों को गंभीर चोटें लगने की खबरें हैं। एक छात्र को तो राहुल गांधी ने पत्रकारों के सामने दिखाया भी था, जिसकी आंख फूटने का खतरा बना हुआ है। एक पत्रकार भी ली पैंलेट गन से चोट लगी है। इसी तरह बिहार में पुलिसकर्मी अभिषेक पटेल के हाथों में एके 47 लेकर छात्रों की तरफ निशाना साधे दिखे हैं, उसके वीडियो सामने हैं, इसी आधार पर उन्हें निलंबित भी किया गया है। तो क्या यह सवाल अमित शाह से नहीं

किया जाएगा कि क्या उन्होंने छात्रों के खिलाफ बंदूकें तानने के आदेश दिया, गोली चलाने के आदेश दिए। अगर नहीं दिए और फिर भी इन हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, तो यह ज्यादा गंभीर बात है कि पुलिस गृहमंत्री को अंधेरे में रखकर काम कर रही है। दोनों ही सूरतों में जवाब अमित शाह को देना पड़ेगा, तभी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन इस समय भाजपा सरकार देश को अंधेरे में रखने का ही काम कर रही है, क्या सरकार यहां जवाब नहीं देगी। अगर कानूनी अदालत में सरकार बोल सकती है, तो फिर जनता के चुने प्रतिनिधि जब यही सवाल उठा रहे हैं, तो जवाब देने से क्यों बच रही है। अगर अमित शाह संसद आते और राहुल गांधी को आमने–सामने जवाब देते तो हंगामा होता ही नहीं। लेकिन भाजपा की रणनीति यही है कि हंगामे की आवाज में जवाबदेही से बचा जाए।संसद के बजट सत्र में भी राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया था, क्योंकि वे चीन से सीमा विवाद पर पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे की किताब को उद्धृत करना चाहते थे। राहुल के भाषण में कई बार व्यवधान उत्पन्न किया गया और उन्हें आखिरकार पूरी बात कहने से रोका गया। इससे पहले शीतकालीन सत्र में एसआईआर पर इसी तरह विपक्ष की बात उठने नहीं दी गई। इस बार राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं तो उनकी सांसदी बनी हुई है। वर्ना पिछले कार्यकाल में तो नरेन्द्र मोदी की कोशिश यही थी कि राहुल गांधी

सदन से ही बाहर हो जाएं। कुछ समय के लिए राहुल गांधी की सांसदी गई भी, उनसे घर भी वापस लिया गया था। लेकिन ये सारे पैंतरे उनकी आवाज को नहीं दबा पाए। फिर भी भाजपा इसी रणनीति पर अटकी हुई है कि किसी तरह राहुल गांधी की आवाज को दबाया जाए। इसके बाद किस तरह से भाजपा यह दावा करती है कि वह लोकतंत्र का सम्मान करती है और संविधान के तहत ही सारे कार्य करती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के खिलाफ तो अविवशाय प्रस्ताव ही लाना पड़ा। उधर साल भर पहले ऐसे ही मानसून सत्र के पहले दिन ही राज्यसभा में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शाम को अचानक इस्तीफे की घोषणा की थी, जिसे फौरन मंजूर भी कर लिया गया था, यह भी देश ने देखा है। अब उनकी जगह सी पी राधाकृष्णन राज्यसभा में आसंदी पर हैं, लेकिन वहां का नजारा बिल्कुल नहीं बदला है। वे भी विपक्ष को अपनी बात पूरी नहीं रखने देते या सत्तापक्ष की टोकाटकी को रोकते नहीं हैं। कुछ मिलाकर संसद के दोनों सदनों में लोकतंत्र बेहाल नजर आ रहा है। विपक्ष के सांसदों को बोलने से रोकने की कोशिश में संसद का महत्वपूर्ण समय नष्ट हो जाता है। विपक्ष के सांसदों को मनजबूर बाहर आकर पत्रकारों से या फिर अलग से प्रेस कांफ्रेंस कर अपनी बात पूरी करनी पड़ती है। भले ही वे बातें संसद की आधिकारिक कार्यवाही में दर्ज न हों, लेकिन जनता के दिमाग में तो दर्ज हो ही रही है, यह मोदी सरकार के लिए ही नुकसानदायक है।



टीवी इंडस्ट्री की सबसे मशहूर अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के साथ—साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहती हैं। बता दें कि उनकी शादी राजा चौधरी के साथ हुई थी लेकिन घरेलू आरोप की वजह से दोनों के रिश्ते में दरार आ गई थी और तलाक ले लिया। दोनों की एक बेटी भी है जो श्वेता के पास रहती है और राजा को अपना पिता तक नहीं मानती। अब हाल ही में ही श्वेता का जीवन फिर से सुर्खियों में आ गया है। बता दें कि राजा चौधरी श्वेता के एक्स हर्षबंद एक पॉडकास्ट में पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने अपने जीवन के बड़े—बड़े राज खोले हैं। इसी के साथ उन्होंने यह भी बताया कि क्यों उन्होंने बेटी की कस्टडी नहीं ली काफी सालों बाद

स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे का भारत का पहला शो हुआ आयोजित, अल्लू सिनेमाज में जुटीं फिल्मी हस्तियां

हैदराबाद ने एक बार फिर देश के सिनेमाई नक्शे पर अपनी अलग पहचान दर्ज कराई है। अल्लू सिनेमाज और सोनी पिक्चर्स इंडिया की ऐतिहासिक साझेदारी के तहत स्पाइडर—मैन ब्रांड न्यू डे का भारत का पहला विशेष शो हैदराबाद में आयोजित किया गया। इस भव्य प्रीमियर को दर्शकों का शानदार समर्थन मिला, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि स्पाइडर—मैन फ्रेंचाइजी के लिए हैदराबाद देश के सबसे बड़े फैनबेस वाले शहरों में शामिल है। वर्षों से स्पाइडर—मैन की फिल्मों को यहां जबरदस्त प्यार मिलता रहा है और इसी वजह से भारत के पहले शो के लिए हैदराबाद को चुना गया। इस खास प्रीमियर में अभिनेता अल्लू अर्जुन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शामिल हुए। उनके अलावा अल्लू अरविंद, अल्लू सिरीश, ऑस्कर विजेता निर्माता गुनीत मोंगा, निर्देशक चंदू मोंडेटी और अल्लू अयान भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की कई प्रमुख हस्तियां ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनमें निर्देशक बोयापति श्रीनु, हरीश शंकर, प्रशांत वर्मा, मारुति, हनु राघवपुडी, पवन सादिनेनी, चंद्रशेखर येलेटी, रवि शंकर यलमंचिली, निर्माता बापी, नंबूरी रवि और साई राजेश नीलम शामिल रहे। इन सितारों की मौजूदगी ने इस प्रीमियर को और



नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो लॉकअप 2 आए दिन नया मोड़ ले रहा है। इस शो में हर दिन कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर इस शो को काफी प्यार दिया जा रहा है। हाल ही में हुए टास्क के दौरान धरीज और सूफी मोतीवाला को बाहर निकाल दिया गया लेकिन हर्षद और योगेश की वापसी के

राजा चौधरी ने इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने बताया कि किस वजह से उन्होंने बेटी की जगह पैसे और प्लैट लेने का फैसला किया। राजा के बताया कि तलाक के केस की वजह से वो काफी कानूनी पचड़ों में पड़ गए थे। ये समय उनके लिए उतना मुश्किल था कि उनके लिए जगह ढूँढना भी मुश्किल हो गया। कुछ समय बाद तो मेरे पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। इतना ही नहीं कोई मुझे घर तक किराए पर देने को तैयार नहीं था। इसके बाद राजा ने बताया की उस समय मैंने और श्वेता ने मिलकर एक प्लैट खरीदा था। मैं और श्वेता मिलकर इसकी ईएमआई चुका रहे थे। तलाक के दौरान राजा ने बस इतना कहा कि मुझे बस प्लेट दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए।



भी खास बना दिया। इस मौके पर निर्माता अल्लू अरविंद ने कहा कि आज के दौर में दर्शकों के पास फिल्म देखने के कई विकल्प हैं, लेकिन शानदार सिनेमाई अनुभव हर जगह नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि जब दर्शकों ने स्पाइडर—मैन को धी—डी में देखने की इच्छा जताई, तो उसी अनुभव को साकार करने के उद्देश्य से अल्लू सिनेमाज की स्थापना की गई। उनका लक्ष्य भारत में विश्वस्तरीय सिनेमाघर अनुभव उपलब्ध कराना और हैदराबाद को देश की नई फिल्म राजधानी के रूप में स्थापित करना है। वरिष्ठ फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने प्रीमियर के बाद अल्लू सिनेमाज की जमकर सराहना की। उन्होंने

मेरे पास रहने तक को जगह नहीं थी...सालों बाद श्वेता तिवारी के एक्स पति ने बताया क्यों छोड़ी उन्होंने बेटी की कस्टडी ?

६६ मैं और श्वेता मिलकर इसकी ईएमआई चुका रहे थे। तलाक के दौरान राजा ने बस इतना कहा कि मुझे बस प्लैट दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा जो भी हमारे पास है वो तुम ले लो।

इसके अलावा जो भी हमारे पास है वो तुम ले लो। इसके बाद राजा ने बताया कि सब कुछ सही चल रहा था और श्वेता भी इस बात के लिए मान गई थी लेकिन इस मामले को बाहर बहुत ही गलत तरीके से दिखाया गया। लोगों को ऐसा लगा कि मैंने बेटी को छोड़कर पैसे को चुना लेकिन कभी भी ऐसा कुछ था नहीं। उन्होंने कभी भी बेटी और संपत्ति में से किसी एक को चुनने जैसी स्थिति नहीं बनाई। उनका कहना है कि वह सिर्फ अपने रहने के लिए एक घर चाहते थे और इसी बात को गलत तरीके से पेश कर दिया गया।



मैं ऋतिक रोशन जैसा दिखता हूं, इसलिए कंगना मेरे पीछे

दिल्ली में चल रहा जंतर—मंतर का प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया लेकिन जुबानी जंग अभी भी बाकी है। अभिनेत्री कंगना ने कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा कथित नीट पेपर लीक मामले को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन की कड़ी आलोचना की उन्होंने प्रदर्शन को हंगामा और अव्यवस्था फैलाने वाला करार दिया। इसके साथ ही कंगना ने कुछ युवा महिलाओं पर भी तीखी टिप्पणियां की और उनके लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं उन्होंने जेन—जी और ब्रच के प्रदर्शन में शामिल लोगों को भी निशाने पर लेते हुए उन पर कई तीखे बयान दिए। इतना ही नहीं इसके कंगना ने खासतौर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर के सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास को खूब खरी—खोटी सुनाई। उन्होंने सौरव को कहा की इस उम्र में मेरे पास कम से कम 2 अवार्ड थे और साथ ही उन्होंने सौरव को बेरोजगार और बेकार कहा। इसके बाद सौरव दास भी चुप नहीं रहे और उन्होंने कंगना को भी सुनाया और साथ ही कंगना की पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ ऐसी बातें बोल दीं, जिसकी वजह से उनका बयान काफी सुर्खियों में आ गया है। कंगना के बयान के बाद सौरव ने उन्हें कहा कि मुझे पता चल गया है कंगना मेरे पीछे क्यों पड़ी है ? मेरे एक दोस्त ने बताया कि शायद वो इसलिए मेरी जान के पीछे पड़ी हैं क्योंकि मैं थोड़ा—बहुत यंग ऋतिक रोशन जैसा दिखता हूं। इसके बाद सौरव ने यह भी साफ कर दिया कि मेरा कंगना के साथ किसी तरह का कोई भी वैर नहीं है। उन्हें बात करने समय थोड़ा सोचना जरूर चाहिए। इसी के साथ उन्होंने अपील करते हुए कहा कि एक—दुसरे को सुनाने के बजाय हमे बैठ कर बात करनी चाहिए। उनके मुताबिक आज कल के युवाओं की वजह से संस्कृति कमजोर पड़ रही है और वहीं दूसरी तरफ वो खुद ही ऐसी बातें कर रही हैं, उन्हें भी थोड़ी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कंगना को भी सलाह दी कि सार्वजनिक मंच पर बयान देते समय शब्दों का चयन सोच—समझकर करें।



कर्नाटक के बाद बेंगलुरु में रुकी ‘जन नायकन’ की स्क्रीनिंग, थिएटरों ने हटाए पोस्टर

कावेरी जल विवाद के चलते कर्नाटक और बेंगलुरु में जन नायकन की स्क्रीनिंग रोक दी गई है। हालात को देखते हुए कई थिएटरों ने एहतिyात के तौर पर शो कैंसिल कर दिए हैं, वहीं कुछ जगहों पर पोस्टर भी हटा दिए गए हैं ताकि कोई गलत घटना न हो। जैसे—जैसे कावेरी पानी को लेकर विवाद बढ़ा, वैसे—वैसे प्रदर्शन भी तेज हो गए। इसके बाद थिएटर मालिकों ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया और ‘जन नायकन’ को सिनेमाघरों से हटा दिया। मंड्या जिले में कुछ कन्नड़ समर्थक संगठनों ने ‘जन नायकन’ के पोस्टर और बैनर भी हटा दिए। बेंगलुरु के संपिगे थिएटर ने पूरे दिन के सभी शो रद्द कर दिए। थिएटर स्टाफ ने विजय के पोस्टर हटाए और कुछ जगहों पर उन्हें दूसरे पोस्टरों से ढक दिया गया। वहीं, श्रीरामपुरा इलाके में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, खासकर उन जगहों पर जहां तमिल भाषी लोगों की संख्या ज्यादा है। यह विवाद तब बढ़ा जब कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक को अगले 15 दिनों तक रोजाना 3,500 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देने का आदेश दिया। इस फैसले का किसान संगठनों और कन्नड़ समूहों ने विरोध किया, उनका कहना है कि कर्नाटक खुद पानी की कमी से जूझ रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा है कि राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी। वहीं तमिलनाडु के कानून मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने कहा कि उनकी सरकार अपने हिस्से का पानी सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। इस बीच कर्नाटक फिल्म चौंबर ने भी इस मामले पर बैठक बुलाने का फैसला किया है, ताकि फिल्म इंडस्ट्री पर पड़ रहे असर पर चर्चा की जा सके। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो एच विनोथ के निर्देशन में बनी ‘जन नायकन’ ने दुनियाभर में 260 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। तमिलनाडु और बेंगलुरु इस कमाई में अहम योगदान दे रहे थे, लेकिन कर्नाटक में स्क्रीनिंग रुकने से फिल्म की कमाई पर असर पड़ सकता है। ‘जन नायकन’ विजय की आखिरी फिल्म मानी जा रही है, क्योंकि इसके बाद वह पूरी तरह राजनीति पर फोकस करने वाले हैं। इस पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा में पूजा हेगड़े, बाँबी देओल, ममिता बैजू, प्रकाश राज, गौतम वासुदेव मेनन और नारायण जैसे कलाकार भी नजर आए हैं।

सक्षिप्त



15 साल के वैभव सूर्यवंशी को उपकप्तान बनाने पर भड़के हर्षा भोगले, बोले- आखिर सोच क्या है?

मुंबई,एजेंसी। दलीप ट्रॉफी 2026–27 के लिए ईस्ट जोन की टीम में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को उपकप्तान बनाए जाने का फैसला चर्चा का विषय बन गया है। युवा बल्लेबाज को ईशान किशन की कप्तानी वाली टीम का उपकप्तान बनाए जाने पर कई पूर्व क्रिकेटरों और विशेषज्ञों ने हैरानी जताई है। मशहूर क्रिकेटर कमेंटेटर हर्षा भोगले भी इस फैसले से सहमत नजर नहीं आए। हर्षा भोगले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि वैभव सूर्यवंशी को सीनियर रेड-बॉल टीम का उपकप्तान बनाने के पीछे क्या सोच रही होगी। उन्होंने 12 पारियों में 17.25 की औसत से 207 रन बनाए हैं। उनकी प्रतिभा असाधारण है, लेकिन रेड-बॉल क्रिकेट में अभी उनके सीखने की शुरुआत ही हुई है। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर तेजी से पहचान बनाई है। हालांकि प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनका अनुभव अभी काफी कम है। उन्होंने अब तक आठ प्रथम श्रेणी मैचों में 207 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 93 रन रहा है। ऐसे में दलीप ट्रॉफी जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में उन्हें उपकप्तानी सौंपने के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। ईस्ट जोन टीम की कप्तानी विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन को सौंपी गई है, जबकि वैभव सूर्यवंशी उपकप्तान होंगे। बल्लेबाजी क्रम में वैभव के अनुभवी बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन के साथ पारी की शुरुआत करने की उम्मीद है। ईस्ट जोन की टीम में भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और मुकेश कुमार भी शामिल हैं, जिससे गेंदबाजी आक्रमण मजबूत नजर आ रहा है। ईस्ट जोन टीमरू ईशान किशन (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी (उपकप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन, सुदीप घरामी, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार, शाहबाज अहमद, सूरज जायसवाल, विराट सिंह, कुमार कुशाग्र, शिखर मोहन, शुभ्रांशु सेनापति, अभिजीत सरकार, अनुकूल रॉय और डेनीश दास।



पीवीसी आयात पर सरकारी पहरा, क्या फिर बिगड़ने वाला है आपके घर का बजट?

नई दिल्ली,एजेंसी। जल्द ही घर बनाना और भी महंगा होने वाला है। खेती के लिए पानी की पाइपलाइन बिछाना या घर की वायरिंग कराना आम आदमी के बजट को बढ़ाने वाला है। सरकार ने सस्ते विदेशी प्लास्टिक कच्चे माल पर नकेल कसने का फैसला किया है। लेकिन इस नीतिगत फैसले का सीधा झटका आम जनता की जेब पर लगने वाला है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने हाल ही में सस्पेंशन — ग्रेड पॉलीविनाइल क्लोराइड (एस-पीवीसी) रेजिन के आयात नियमों को सख्त कर दिया है। यह एक तरह का प्लास्टिक कच्चा माल है, जिसका इस्तेमाल घरों में इस्तेमाल होने वाले पानी के पाइप, बिजली के तारों की कोटिंग, खिड़कियों की फ्रेम, प्लास्टिक पैकिंग, कई चिकित्सा उत्पादों और यहां तक कि जूतों के सोल बनाने में होता है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि इस कदम से घरेलू पीवीसी रेजिन की कीमतों में बड़ोतरी की आशंका है। भारत ने वित्त वर्ष 2025–26 में 1.63 अरब डॉलर का रेजिन आयात किया था। चीन सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था, इसके बाद जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, इंडोनेशिया, थाइलैंड, अमेरिका, सिंगापुर एवं वियतनाम का स्थान रहा। जीटीआरआई के मुताबिक, इन देशों से आयात की औसत कीमत 0.65 डॉलर से 0.75 डॉलर प्रति किलोग्राम के बीच रही, जो डीजीएफटी की तय राशि 0.76 डॉलर से कम है। ऐसे में मौजूदा आयात का बड़ा हिस्सा अब अंकुश के दायरे में आ जाएगा। घर बनाने में पीवीसी पाइप, फिटिंग और बिजली के तारों की बड़ी खपत होती है। जब कच्चा माल महंगा होगा, तो कंपनियां इसका बोझ सीधे ग्राहकों पर डालेंगी। खेती- किसानी और पानी की पाइपलाइनों में 70 से 80 फीसदी पीवीसी का इस्तेमाल होता है। पाइप महंगे होने से किसानों का बजट बिगड़ेगा। इस कच्चे माल का इस्तेमाल पैकेजिंग फिल्मों और आम जूतों-चप्पलों में भी होता है, जिससे दैनिक उपयोग की कई वस्तुएं महंगी हो सकती हैं। भारत में पीवीसी पाइप और केवल बनाने वाली हजारों छोटी और मझोली इकाइयां हैं। सस्ता माल न मिलने से उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। इसका असर दोतरफा होगा, या तो उत्पाद महंगे होंगे, या फिर कई छोटी इकाइयां बंद होने के कगार पर पहुंच जाएंगी। देश कुल जरूरत का 64 फीसदी एस-पीवीसी रेजिन आयात करता है।

हल्की बढ़त के साथ शेयर बाजार की शुरुआत, सेंसेक्स 49 अंक चढ़ा, निफ्टी 24350 के करीब

मुंबई,एजेंसी। घरेलू शेयर बाजार ने शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त के साथ शुरुआत की। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 49.91 अंक चढ़कर 77,970.95 अंक पर पहुंच गया। वहीं, एनएसई निफ्टी भी 28 अंक की बढ़त के साथ 24,343.65 अंक पर कारोबार कर रहा था। विदेशी निवेश बढ़ने और दुनियाभर में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में रुपया मजबूत हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया 20 पैसे चढ़कर 95.30 के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, डॉलर के मजबूत होने से रुपये की बढ़त सीमित रही। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने यह जानकारी दी। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 95.40 के स्तर पर खुला। बाद में इसमें मजबूती आई और यह 95.30 के स्तर पर पहुंच गया।

खेल

मुक्केबाज प्रीति पवार फाइनल में, स्वर्ण पदक से एक कदम दूर, डेकाथलॉन में तेजस्विन का जलवा

ग्लासगो,एजेंसी। भारत ने 4X400 मीटर रीले के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दो हीट्स में कुल 13 टीमें थीं। पहली हीट से नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, जमैका और जाम्बिया ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। वहीं, दूसरी हीट में टीम इंडिया चौथे स्थान पर रहकर फाइनल में पहुंची। फाइनल में आठ टीमें उतरती हैं। दोनों हीट से सर्वश्रेष्ठ तीन टीमें डायरेक्ट क्वालिफाई करती हैं, जबकि बाकी टीमों से बेस्ट टाइम वाली दो टीमें फाइनल में पहुंचती हैं। इसीमें भारत ने क्वालिफाई किया। इसका फाइनल एक अगस्त को खेला जाएगा। 4X400 रीले भारतीय टीम में विशाल थेन्नारासू, अंसा बाबू, राजेश रमेश और रशदीप कौर हिस्सा हैं। डेकाथलॉन का सातवां इवेंट भी हो चुका है। डिस्कस थ्रो में तेजस्विन छठे स्थान पर रहे। हालांकि, सातों इवेंट को मिला दिया जाए तो तेजस्विन के 5935 अंक हैं और वह फिलहाल दूसरे स्थान पर हैं। पहले स्थान

पर मौजूद कनाडा के डेमियन वॉर्नर से तेजस्विन के सिर्फ तीन अंक कम हैं और तेजस्विन अगले तीन इवेंट में स्वर्ण पदक के बारे में सोच सकते हैं। डेमियन के 5938 अंक हैं। आज ही बाकी के तीन इवेंट भी खेले जाएंगे। भारत की स्टार मुक्केबाज प्रीति पवार महिलाओं के 54 किग्रा भार वर्ग में फाइनल में पहुंच चुकी हैं। उन्होंने 5—0 से जाम्बिया की मुक्केबाज कैथरीन मवापे को शिकस्त दी। यानी प्रीति ने सर्वसम्मति से जीत हासिल की। पहले, दूसरे और तीसरे, तीनों राउंड में पांच जजों ने प्रीति को 10—10 अंक दिए। 2022 एशियाई खेलों की गोल्ड मेडलिस्ट प्रीति अब स्वर्ण पदक से एक कदम दूर हैं। मुक्केबाजी में भारत की प्रीति पवार 54 किग्रा भार वर्ग के सेमीफाइनल में जाम्बिया की कैथरीन मवापे से भिड़ रही हैं। पहला राउंड प्रीति ने सर्वसम्मति से जीत लिया है। सभी पांच जजों ने प्रीति के पक्ष में फैसला दिया। डेकाथलॉन का आज छठा इवेंट था, जिसमें तेजस्विन दूसरे स्थान पर रहे। यह इवेंट 110 मीटर हर्डल्स यानी बाधा दौड़



रहा। इसमें कनाडा के डेमियन वॉर्नर 14.04 सेकंड के समय के साथ पहले स्थान पर रहे। वहीं, तेजस्विन ने 14.41 सेकंड का समय लिया। डेकाथलॉन में सभी एथलीट 10 अलग-अलग स्पर्धाओं में हिस्सा लेते हैं। फिलहाल छह इवेंट के बाद डेमियन के कुल अंक 5322 हैं और वह पहले स्थान पर हैं। वहीं, तेजस्विन 5261 अंक लेकर दूसरे स्थान पर हैं। वह डेमियन से 61 अंक पीछे हैं। इसके बाद

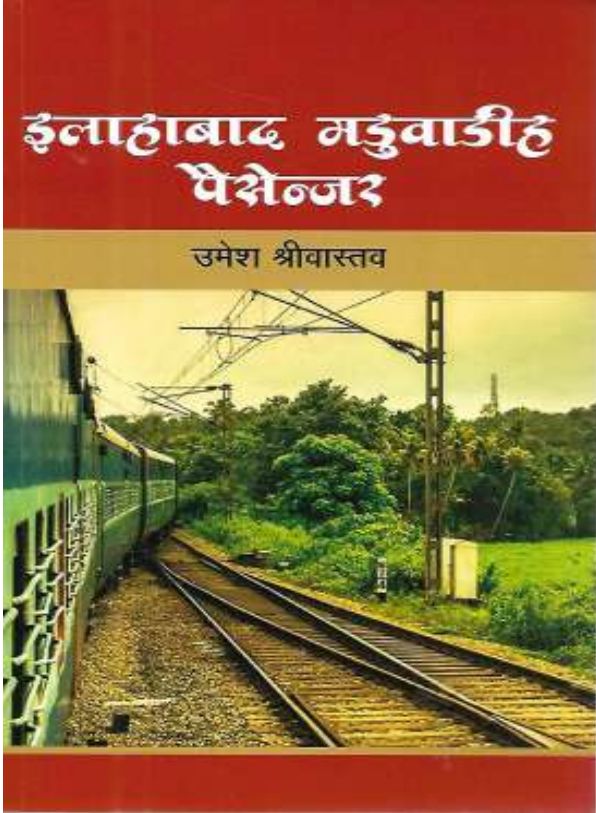
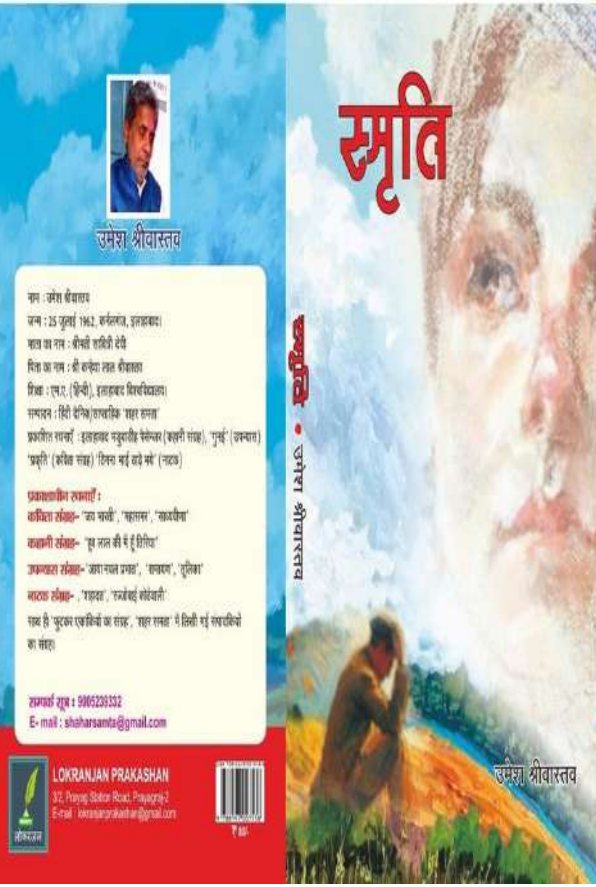
डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट और जेवलिन थ्रो और 1500 मीटर रेस के इवेंट्स बाकी हैं। डेकाथलॉन स्टार तेजस्विन शंकर पूरे दिन अलग-अलग स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। आज भारत के अभियान की शुरुआत भी वही करेंगे। सबसे पहले वह 110 मीटर बाधा दौड़ में उतरेंगे। इसके बाद डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो और 1500 मीटर दौड़ के बाद डेकाथलॉन पदकों का फैसला होगा। इसके

अलावा मिश्रित 4*400 मीटर रिले और पुरुष 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में भी भारतीय खिलाड़ी मेडल की चुनौती पेश करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय जूडो टीम भी शुक्रवार से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। हर्ष सिंह, श्रद्धा चोपड़े, रोहित बसीर माजगुल, अस्मिता डे और यामिनी मौर्य अपने शुरुआती मुकाबले खेलेंगे। जीतने पर वे शाम के सत्र में अगले दौर में उतरेंगे। भारतीय

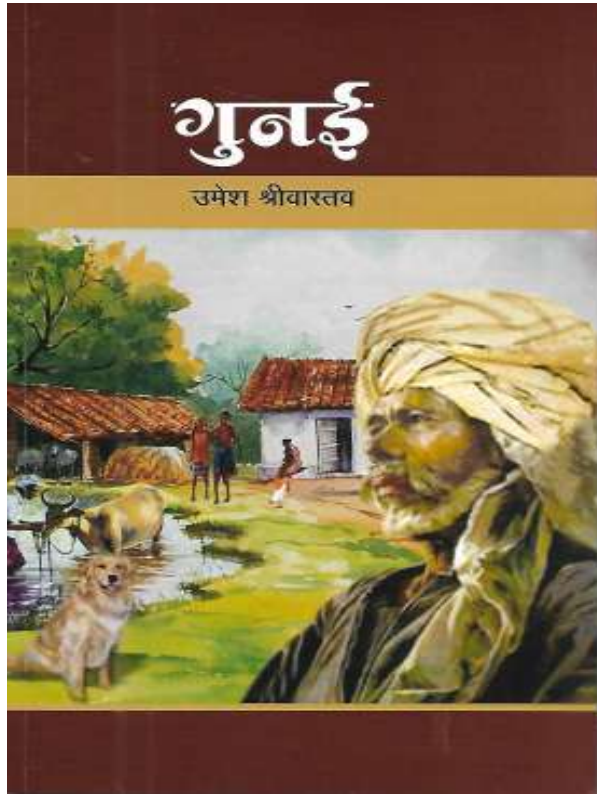
मुक्केबाजों के लिए यह दिन बेहद अहम है। ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन समेत कुल 10 भारतीय मुक्केबाज सेमीफाइनल मुकाबले खेलेंगे। जीत हासिल करने पर वे फाइनल में पहुंचेंगे और कम से कम रजत पदक सुनिश्चित कर लेंगे। भारत के पास सैद्धांतिक रूप से बॉक्सिंग में 10 स्वर्ण पदक जीतने का मौका भी बना हुआ है।

दर्जी का बेटा बना हेवी-वेट हीरो, पिता ने कैंची-धागे से नहीं, हौसले से गढ़ा लवप्रीत का सपना

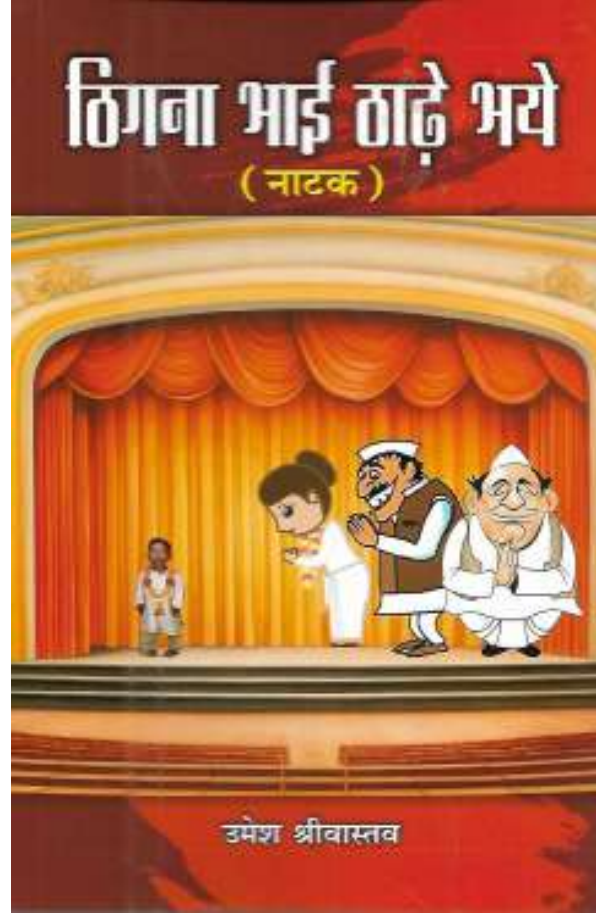
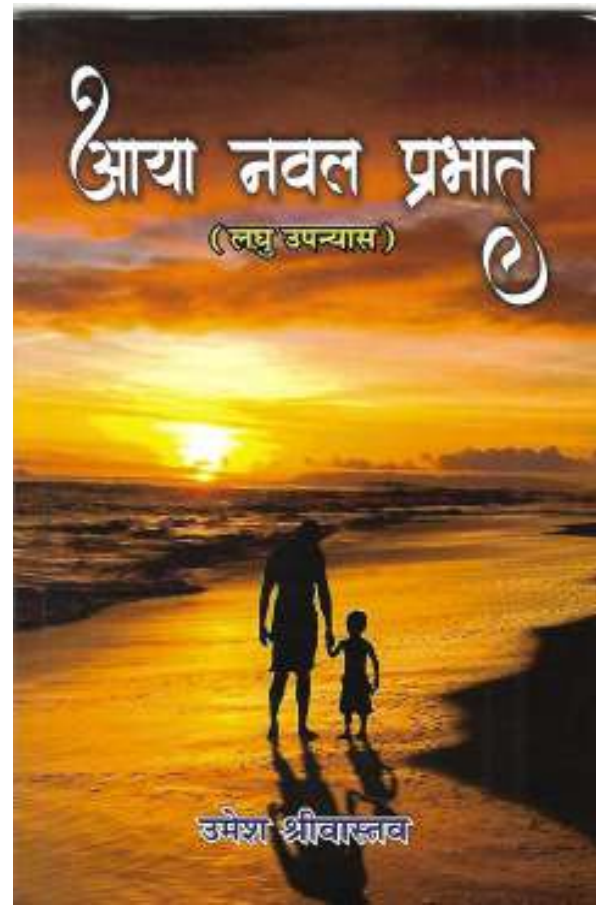
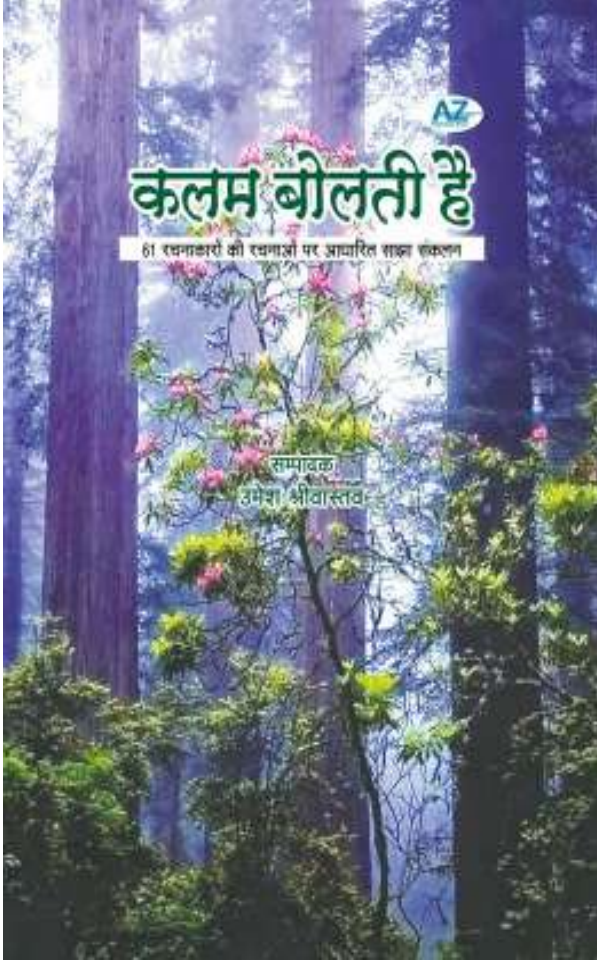
ग्लासगो,एजेंसी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जब भारत के लवप्रीत सिंह ने स्नैच में 176 किलोग्राम वजन उठाकर नया गेम्स रिकॉर्ड बनाया, तब सिर्फ एक पदक नहीं जीता गया था, बल्कि एक ऐसे परिवार का संघर्ष भी दुनिया के सामने आया जिसने आर्थिक मुश्किलों के बावजूद अपने बेटे के सपनों को कभी छोटा नहीं होने दिया। पंजाब के अमृतसर जिले के सीमावर्ती गांव बल सिकंदर से आने वाले लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम भारवर्ग में 388 किलोग्राम (176212) का कुल भार उठाकर रजत पदक अपने नाम किया। वह सिर्फ एक किलोग्राम से स्वर्ण पदक से चूक गए। न्यूजीलैंड के डेविड एंड्रयू लिटी ने 389 किलोग्राम के साथ स्वर्ण जीता। लवप्रीत का परिवार बेहद साधारण है।



समूह के लोकप्रिय साहित्यकार श्री उमेश श्रीवास्तव जी का कहानी संग्रह इलाहाबाद मडुवाडीह पैसेंजर प्रकाशित हो गया है। उमेश श्रीवास्तव जी को बहुत बधाई एवम शुभकामना।



चर्चित कथाकार और शहर समता अखबार के संपादक श्री उमेश श्रीवास्तव जी का ग्रामीण पृष्ठभूमि पर लिखा बहु प्रतीक्षित



ठिगना भाई ठाढ़े भये (Thigna Bhai Thade Bhaye)

संक्षिप्त

जापान में तबाही का मंजर: भूकंप के बाद मौत का आंकड़ा 34 पहुंचा, हजारों लोग राहत शिविरों मेंय बचाव अभियान जारी

कुमामोटो, एजेंसी। कुमामोटो प्रांत सरकार ने शुक्रवार को बताया कि दक्षिण–पश्चिमी जापान में आए शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। इस भूकंप के कारण एक मौल में विस्फोट हुआ, एक कारखाने की चिमनी



गिर गई और कई घर ध्वस्त हो गए। कितने लोग घायल हैं? बता दें कि मंगलवार को जापान के दक्षिणी मुख्य द्वीप क्यूशू में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। अधिकारियों ने बताया कि आपदा से संबंधित 34 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं, एक अन्य मौत की जांच अभी जारी है। गुरुवार को अधिकारियों ने बताया कि 80 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें से पांच गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं, 3,500 से अधिक घरों में अभी भी बिजली नहीं थी। 9,000 से अधिक लोग आश्रय स्थलों में रह रहे थे, जहां वायु कंडीशनिंग प्रदान करने के लिए बिजली के स्रोत जोड़े जा रहे थे। भूकंप के बाद से, भीषण गर्मी सहित कई बीमारियों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। बचाव कार्य जारी शुक्रवार को कुमामोटो क्षेत्र में बचाव कार्य जारी रहा, जिसमें काशिमा कस्बे में ढह चुके एयॉन मॉल शॉपिंग सेंटर का स्थल भी शामिल था, जहां सबसे अधिक नुकसान दर्ज किया गया था। भूकंप के समय यह परिसर हजारों लोगों से भरा हुआ था। 3,000 खरीदारों को पार्किंग से निकाला कंपनी ने बताया कि मॉल के दूसरे हिस्से में विस्फोट होने से पहले लगभग 3,000 खरीदारों को पार्किंग स्थल पर सुरक्षित निकाल लिया गया था। विस्फोट के दौरान मॉल के कुछ कर्मचारी काम करते रहे। विस्फोट के बाद मॉल की दूसरी मंजिल ढह गई, जिससे लोग अंदर फंस गए। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव मिनेोरु किहारा ने शुक्रवार को टोक्यो में पत्रकारों को बताया कि घटनास्थल पर सात लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 11 लोगों को बचा लिया गया है। अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि कितने लोग अभी भी लापता हैं। इस बीच, किहारा ने बताया कि यात्सुशिरो क्षेत्र में निप्पॉन पेपर इंडस्ट्रीज के एक कारखाने में भूकंप के दौरान चिमनी गिरने के बाद तलाशी अभियान समाप्त हो गया है। बचाव दल ने वहां से 11 लोगों को बचाया, जबकि नौ अन्य लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।

अमेरिका में पढ़ाई के बाद नौकरी करना होगा महंगा, ट्रंप प्रशासन के नए प्रस्ताव से भारतीयों की बढ़ेगी चिंता ?

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में पढ़ाई करने वाले विदेशी छात्रों के लिए आने वाले समय में नौकरी करना काफी महंगा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन अमेरिकी विश्वविद्यालयों से पढ़ाई पूरी करने के बाद काम करने की अनुमति देने वाले ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ओपीटी) कार्यक्रम पर 1 लाख अमेरिकी डॉलर (करीब 87 लाख रुपये) की फीस लगाने पर विचार कर रहा है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के पास विचाराधीन प्रस्ताव द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रस्ताव अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) के स्तर पर विचाराधीन है। हालांकि विभाग ने साफ किया है कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। विभाग का कहना है कि जब तक किसी नीति की आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक उसे अंतिम नहीं माना जाना चाहिए। क्या है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्कीम? ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कार्यक्रम विदेशी छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में एक से तीन साल तक अपने विषय से जुड़े क्षेत्र में काम करने की अनुमति देता है। यही सुविधा बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अमेरिका में पढ़ाई के लिए आकर्षित करती है। वर्ष 2024 में करीब 4.19 लाख विदेशी छात्र ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के तहत अमेरिका में काम कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन इससे पहले २–1८ वीजा पर भी 1 लाख डॉलर की फीस लगाने की योजना बना रहा था, लेकिन अमेरिकी अदालत ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद अब ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर इतनी बड़ी फीस लगाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। भारतीय छात्रों पर पड़ सकता है असर
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी विदेश विभाग विदेश से ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वालों पर भी 1 लाख डॉलर का बॉन्ड लगाने पर विचार कर रहा है। यह राशि तब वापस की जा सकती है, जब आवेदक अमेरिका जाकर नागरिकता हासिल कर ले। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ओपीटी पर इतनी अधिक फीस लागू होती है तो अमेरिका में पढ़ने की योजना बना रहे हजारों विदेशी छात्रों, खासकर भारतीय छात्रों पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है।

ट्रंप प्रशासन बंद करेगा मेडिकेयर दवा सब्सिडी योजना, 2027 से लाखों बुजुर्गों का बढ़ सकता है खर्च

वॉशिंगटन , एजेंसी। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने मेडिकेयर के तहत दी जाने वाली एक अस्थायी दवा सब्सिडी योजना को बंद करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद 2027 से लाखों बुजुर्गों को अपनी प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के लिए हर महीने अधिक पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। यह योजना 2024 में तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन ने शुरू की थी।

आवश्यकता है

उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले से प्रकाशित समाचार पत्र को समस्त जनपदों में एवम तहसील व ब्लॉक/ शहर में ब्यूरो प्रमुख, चीफ रिपोर्टर, संवाददाता, प्रतिनिधि मण्डल की अवश्यकता है जिन्हे आकर्षण वेतन और भत्ते आदि सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

सम्पर्क सूत्र

शहर समता हिन्दी दैनिक/ साप्ताहिक समाचार पत्र

मोबाईल नम्बर 9190052 39332

919450482227

विदेश

पाकिस्तान के ब्रॉड पीक पर एवलांच: निम्सदाई समेत छह लापता , चार शव बरामद ,सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के उत्तरी हिस्से में काराकोरम पर्वत श्रृंखला स्थित दुनिया की 12वीं सबसे ऊंची चोटी ब्रॉड पीक पर गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। चोटी पर चढ़ाई के दौरान आए भीषण हिमस्खलन (एवलांच) की चपेट में आने से नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल पुरजा (निम्सदाई) समेत छह अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोही लापता हो गए हैं। वहीं, अब तक चार शव बरामद किया गया है। हादसे के बाद पूरे पर्वतारोहण जगत में चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तानी प्रशासन और अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान (एसीपी) ने खोज एवं बचाव अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन खराब मौसम अभियान में बड़ी चुनौती बना हुआ है। एवलांच के बाद टीम से टूटा

संपर्क स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, हादसा उस समय हुआ जब पर्वतारोहियों का दल ब्रॉड पीक की चोटी की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान अचानक भारी हिमस्खलन आ गया। इसके बाद टीम से संपर्क पूरी तरह टूट गया। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के उपाध् यक्ष करार हैदरी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पर्वतारोहियों की तलाश के लिए सभी संबंधित एजेंसियों को अलर्ट



कर दिया गया है। कौन–कौन पर्वतारोही हैं लापता? अधि कारियों के अनुसार, लापता दल में कई देशों के अनुभवी पर्वतारोही शामिल हैं। इनमें नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल पुरजा (निम्सदाई) समेत पांच नेपाली पर्वतारोही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के हुंजा क्षेत्र के पर्वतारोही सोहेल सखी, अमेरिका की मैलोरी गेस, चीन के वांग, ओमान की नथिरा और एक अन्य विदेशी पर्वतारोही भी लापता

`ढह चुका है पाकिस्तान का सिस्टम': गृह मंत्री मोहसिन नकवी का कबूलनामा, क्यों कही यह बात ?

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने देश की बدهाल स्थिति पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि पाकिस्तान की मौजूदा शासन–व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और अब यह देश की चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं है। इस्लामाबाद में आयोजित पहले श्पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट्स को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि जिस व्यवस्था में हम रह रहे हैं, वह ढह चुकी है। मानो या न मानो आप इस व्यवस्था को 70 साल से घसीट रहे हैं, और जबकि हम सब लोकतंत्र चाहते हैं, लोकतंत्र के अंदर कई रूप होते हैं। मौजूदा व्यवस्था के जरिए समस्याएं हल नहीं हो सकतीं। “ क्या प्रशासनिक सुधारों से बदलेगी पाकिस्तान की तस्वीर?

गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने देश में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक सुधारों की वकालत की है। उन्होंने नए प्रशासनिक निकायों और नई इकाइयों के गठन पर जोर दिया। नकवी की यह मांग पाकिस्तान के कई प्रमुख राजनीतिक दलों की उस पुरानी मांग से मेल खाती है, जिसमें बेहतर शासन संचालन के लिए देश में अधिक प्रांत बनाने की बात कही जाती रही है। नकवी के इस बयान से साफ है कि पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व भी अब यह मानने लगा है कि मौजूदा ढर्रे पर देश को आगे चलाना नामुमकिन है। रिकॉर्ड कर्ज का बोझ और विदेशी मुद्रा भंडार का संकट पाकिस्तान इस समय अपने इतिहास के सबसे भीषण आर्थिक दौर से गुजर रहा है। देश का कुल विदेशी कर्ज लगभग 137 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है, जिसमें आईएमएफ का ही 8.8 अरब डॉलर है। यह कुल सरकारी कर्ज जीडीपी का करीब 70: से



80: तक पहुंच गया है। हालात यह है कि पाकिस्तान सरकार के बजट का एक बड़ा हिस्सा (लगभग दो–तिहाई) केवल पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में ही चला जाता है। देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम बचा है कि वह बिना किसी बाहरी वित्तीय मदद के कुछ महीनों का आयात भी नहीं संभाल सकता।

पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को वेंटिलेटर से बाहर निकालने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की शरण में जाने के लिए मजबूर है। आजादी से लेकर अब तक पाकिस्तान 25 बार आईएमएफ से बेलआउट पैकेज (कर्ज) ले चुका है। आईएमएफ की सख्त शर्तों (जैसे टैक्स बढ़ाना,

नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा पर PM बालेन की शांति की अपील, दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा

काठमांडू। नेपाल के मधेश प्रांत में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच भड़की सांप्रदायिक हिंसा में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री बालेन शाह ने शांति बनाए रखने की अपील करते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। कई जिलों में कर्फ्यू लागू है, जबकि विपक्ष सरकार पर संकट से निपटने में विफल रहने का आरोप लगा



रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने देश के दक्षिण–पूर्वी मधेश प्रांत में फैली सांप्रदायिक हिंसा के बीच लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच शुरू हुई झड़पों में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई पुलिसकर्मी और आम लोग घायल हुए हैं। हालात को देखते हुए कई इलाकों में कर्फ्यू और निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। प्रधानमंत्री बालेन शाह ने राष्ट्र के नाम संबोध्ान में कहा कि सरकार इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। उन्होंने हिंसा में मारे गए जय प्रकाश मेहता, ओम प्रकाश मेहता और गणेश यादव के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के बाद कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि गृह मंत्रालय ने घटना की जांच के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को सभी घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से अफवाहें, अपुष्ट जानकारी या सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाली सामग्री साझा न करें। सरकार पर लापरवाही के आरोप हिंसा बढ़ने के बाद विपक्ष ने प्रधानमंत्री शाह की सरकार पर निष्क्रिय रहने का आरोप

लगाया है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार ने समय रहते सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई और राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व दिखाए में विफल रही। आलोचकों ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बुधवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि, गुरुवार को प्रधानमंत्री बालेन शाह ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से मुलाकात कर उन्हें सुरक्षा स्थिति की जानकारी दी। कई जिलों में तनाव, कर्फ्यू लागू

मधेश प्रांत के सिराहा, धनुषा और सुनसरी समेत कई जिलों में गुरुवार को भी तनाव बना रहा। सिराहा के गोलबाजार और लहान तथा धनुषा के जनकपुरधाम में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुईं। सिराहा में गोली लगने से किशोर गणेश यादव की मौत हो गई। वहीं सुनसरी में पहले हुई हिंसा में घायल जय प्रकाश मेहता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इससे पहले ओम प्रकाश मेहता की भी मौत हो चुकी थी। हिंसा के दौरान आगजनी की घटनाएं भी सामने आईं। हालात को देखते हुए सिराहा और जनकपुरधाम के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया, जबकि भारत से सटे पर्सा जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई है। कैसे शुरू हुआ विवाद? यह हिंसा 26 जुलाई को सुनसरी जिले के देवानगंज ग्रामीण नगरपालिका के कप्तानगंज इलाके में शुरू हुई। सावन महीने में बोलबम यात्रा के दौरान हिंदू श्रद्धालु डीजे बजाते हुए पवित्र जल लेकर जा रहे थे। पुलिस के अनुसार, तेज आवाज में बज रहे डीजे का कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध किया। पहले दोनों पक्षों में बहस हुई, जो बाद में मारपीट और हिंसा में बदल गई। देखते ही देखते दोनों समुदायों के बड़ी संख्या में लोग लाठी, पत्थर, बांस और लोहे की रॉड लेकर मौके पर पहुंच गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसी दौरान पुलिस की गोली लगने से ओम प्रकाश मेहता की मौत हो गई। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक गुरुवार को प्रधानमंत्री बालेन शाह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी) की बैठक भी हुई। बैठक में नेपाल की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई और फैसला लिया गया कि सुरक्षा एजेंसियों तथा अन्य संबंधि त संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय बढ़ाया जाएगा, ताकि सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता बनाए रखी जा सके।

अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक अभियान पूरा नहीं हो जाता, तब तक सभी संभावनाओं पर काम किया जाएगा। कौन हैं निम्सदाई?

निर्मल पुरजा, जिन्हें दुनिया शनिम्सदाईश् के नाम से जानती है, नेपाल के सबसे चर्चित पर्वतारोहियों में गिने जाते हैं। उन्होंने 2019 में महज साढ़े छह महीने के भीतर दुनिया की 8,000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ाई पूरी कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। पर्वतारोहण में उनके योगदान के कारण उनका नाम दुनिया के सबसे सफल हाई–एल्टीट्यूड क्लाइंबर्स में शामिल है। ऐसे में उनके लापता होने की खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान इस हादसे की ओर खींच लिया है। ब्रॉड पीक क्यों माना जाता है खतरनाक? ब्रॉड पीक पाकिस्तान और चीन की सीमा के पास काराकोरम पर्वत श्रृंखला में

स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,047 मीटर है और यह दुनिया की 12वीं सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अत्यधिक ऊंचाई, अचानक बदलता मौसम, गहरी बर्फ और हिमस्खलन का खतरा इसे दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण पर्वत चोटियों में शामिल करता है। हर साल यहां दुनिया भर से अनुभवी पर्वतारोही पहुंचते हैं, लेकिन मौसम खराब होने पर यह चोटी बेहद खतरनाक साबित होती है। फिलहाल क्या है स्थिति? फिलहाल छह पर्वतारोही लापता हैं उनकी तलाश जारी है। वहीं चार शव को बरामद कर लिया गया है। प्रशासन ने किसी के सुरक्षित मिलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। बचाव दल मौसम में सुधार का इंतजार करते हुए लगातार अभियान चला रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हुई है।

मोरक्को की सीमा तोड़कर स्पेन में घुसे हजारों प्रवासी: 18 की मौत, मचा हड़कंप, यूरोप के सामने खड़ा हुआ नया संकट ?

स्पूटा, एजेंसी। मोरक्को से हजारों प्रवासी गुरुवार को स्पेन के छोटे से स्वायत्त क्षेत्र स्पूटा में पहुंच गए। सीमा पार करते समय मची अफरा–तफरी में 18 लोगों की मौत भी हो गई। इसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने स्पेन सरकार से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने और सीमा पर स्थिति संभालने के लिए सेना भेजने की मांग की। स्पेन के गृह मंत्रालय ने कहा कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा और देश की सीमा की रक्षा सुनिश्चित करेगा। हालांकि, सरकार प्रवास से जुड़ी चिंताओं को लेकर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं कर सकती। राशिद सबीही स्पूटा में स्पेन की सिविल गार्ड के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन के प्रमुख हैं। उन्होंने बताया कि स्थिति पूरी तरह अराजक है। उन्होंने कहा, सटीक संख्या बताना संभव नहीं है, लेकिन हजारों प्रवासी सीमा पार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सीमा की स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी है। उत्तरी मोरक्को में मानवाधिकार संगठन के सदस्य अशरफ मैमौनी ने स्थिति को श्असाधारणश् बताया। उन्होंने कहा, आज सुबह ताराजल सीमा को असामान्य हालात में खोला गया और लोग वहां से अंदर आ गए। वीडियो फुटेज में दिखाया गया कि बड़ी संख्या में लोग ताराजल समुद्र तट के किनारे बने तटबंधों से होते हुए स्थानीय सड़कों पर पहुंच रहे थे। इनमें ज्यादातर मोरक्को के नागरिक थे। ज्यादातर युवा पुरुष डिफाई दे रहे थे, लेकिन महिलाओं और बच्चों वाले परिवार भी शामिल थे। कुछ लोगों ने एसोसिएटेड प्रेस के लिए काम कर रहे एक स्वतंत्र फोटोग्राफर को देखकर श्विया एस्पानाश् (स्पेन जिंदाबाद) के नारे भी लगाए। अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि इतनी बड़ी संख्या में प्रवासियों के स्पूटा पहुंचने की वजह क्या थी। स्पेन–मोरक्को सीमा पर क्यों बढ़ा संकट? स्पेन और मोरक्को की सीमा पर यह तनाव बुधवार को छोटे से स्पेनिश क्षेत्र में पहुंचने की कोशिश कर रहे प्रवासियों की संख्या बढ़ने के बाद बढ़ा। इनमें से ज्यादातर लोग समुद्र में तैरकर स्पूटा पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। सबीही और मोरक्को तथा स्पूटा के सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुसार, बुधवार को समुद्र के रास्ते स्पूटा पहुंचने की कोशिश में तीन लोगों की मौत हो गई।

पाकिस्तान की कोयला खदान में बड़ा हादसा, धमाके में 32 मजदूरों की मौत, 10 अब भी फंसे

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के दक्षिण–पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित एक कोयला खदान में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 32 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य मजदूर अब भी जमीन के नीचे फंसे हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक उनकी स्थिति बेहद गंभीर मानी जा रही है और राहत–बचाव अभियान लगातार जारी है। धमाका कैसे हुआ? सरकारी खदान निरीक्षक गनी बलोच के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि विस्फोट मिथेन गैस के अत्यधिाक जमा होने के कारण हुआ। हादसे के कुछ घंटों बाद पहले सात मजदूरों के शव निकाले गए, जबकि बाद में चार और शव बरामद किए गए। गनी बलोच ने बताया कि राहत अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक सभी फंसे मजदूरों का पता नहीं चल जाता। हालांकि उन्होंने आशंका जताई कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि मिथेन गैस विस्फोट के बाद ऑक्सीजन का स्तर लगभग शून्य हो जाता है, जिससे किसी के जीवित मिलने की संभावना लगातार कम होती जाती है।

प्रतापगढ़ ब्यूरो
शरद कुमार श्रीवास्तव
 7/31, अचलपुर, प्रतापगढ़
संस्थापक
स्व.कन्हैया लाल स्व.श्रीमती साधना सम्पादक
उमेश चंद्र श्रीवास्तव प्रबन्ध सम्पादक
अरविन्द पाण्डेय संयुक्त सम्पादक
अनंत श्रीवास्तव संयुक्त सम्पादक
(तकनीकी)
केशव श्रीवास्तव विधि सलाहकार
कल्पना श्रीवास्तव

शहर समता
स्वामी/प्रकाशक/मुद्रक/सम्पादक
 उमेश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा कम्पीटेन्ट बिजनेस सर्विसेज, विष्णु पदम कुटीर 115डी/2ई ल्कुरांज, इलाहाबाद से मुद्रित कराकर 289/238ए,कर्नलगंज इलाहाबाद से प्रकाशित
सम्पादक
उमेश चन्द्र श्रीवास्तव
मो.नं.9005239332
आर.एन.आई.नं.
यूपीएचआईन/2004/22466
Email : shaharsamta@gmail.com
इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद इलाहाबाद न्यायालय के अधीन ही होंगे।